*अनावृत अर्थव्यवस्था**

रघुराम जी. राजन

एनडीटीवी : नमस्ते, आपका स्वागत है। वाकई में मैं आज स्वयंको गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मेरे पैनल पर दो महानुभाव उपस्थित हैं जिनसे हम प्रश्न करने वाले हैं और यह जानना चाहेंगे कि उनके दिमाग में क्या है। मैं, और आप सभी इन दोनों विद्वानों से भलीभांति परिचित हैं। यहां पर पूरे देश से आये हुए विद्यार्थीगण, सेंट स्टीफन्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, एलएसआर और नामी-गिरामी, महाविद्यालयों के विद्यार्थी। हम यहां पधारे भारतीय रिज़र्व के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन जी को धन्यवाद देते हैं। यहां उनके एक दोस्त भी उपस्थित हैं जो उनसे शायद कभी सहमत होते हों, श्री अरविंद सुब्रमणियन जी, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार। शायद मुझे इस प्रकार से कभी कहने को मौका नहीं मिलता है लेकिन आज पूरी ईमानदारी से जरूर कहूंगा कि आज हमारे साथ दो महान पेशेवर, विश्व भर में सम्मानित और इस देश की अर्थव्यवस्था के संचालक विद्वान उपस्थित हैं। सच तो यह है कि देश में सब कुछ गडमड हो चुका है और इसके पीछे आपकी गलती नहीं है। इसके बरअक्स, कुछ भी गडमड नहीं हुआ है लेकिन क्या किसी बात पर आप दोनों एक-दूसरे से हमेशा सहमत हुए हैं ? आप दोनों दोस्त हैं लेकिन दोनों का रिश्ता धर्म और राजनीति जैसा है।

रघुराम राजन : नहीं, हम असहमत भी होते हैं।

एनडीटीवी : आप असहमत भी होते हैं।

रघुराम राजन : जी हां, आर्थिक नीतियों के संबंध में होते हैं।

अरविंद सुब्रमणियन : और कभी-कभी तो ज़ोरदार विरोध करते हैं ।

रघुराम राजन : लेकिन ऐसे मामलों में जहां बहुत बड़ी योजनाएं जैसी चीजें हो न कि मौजूदा नीति के संबंध में, आप इसे मोटे तौर पर यूं कह सकते हैं कि दीर्घकाल में संवृद्धि की दिशा और उससे जुड़ी चीजों के बारे में।

अरविंद सुब्रमणियन : और यदि हम दोनों किसी अवसर पर जोरदार तरीके से एक-दूसरे से असहमत नहीं हुए तो मैं समझता हूँ कि उसका आउटपुट बहुत कम निकलेगा।

एनडीटीवी : जब हम जवान थे तब इस तरह की स्थिति को द्वंद्ववाद कहते थे और आप लोग द्वंद्ववाद के माध्यम से तरक्की का रास्ता निकाल रहे हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ? जब आप दोनों आईएमएफ में थे तब आपने मिलकर काफी बड़ा पेपर लिखा था, और जिसपर खूब विवाद हुआ था और यह सब अरविंद साहब की गलती थी, क्या मैं सही कह रहा हूँ ?

रघुराम राजन : जी हां, उन्होंने ही पेपर लिखा था।

एनडीटीवी :जो भी हो, आप संयुक्त लेखक तो थे ही ?

रघुराम राजन : हम उस पेपर के संयुक्त लेखक हैं । हमने इसे मिलकर लिखा था, उस पेपर का विषय आर्थिक सहायता से संबंधित था जिसकी कहानी यह थी कि आर्थिक वृद्धि के लिए वस्तुतः आर्थिक सहायता से काम नहीं चलता है। ऐसी सहायता प्राकृतिक आपदा के समय उपयोगी होती है, लेकिन यदि इतनी सारी रकम आप सहायता के नाम पर डाल देंगे तो आपको इस बात के कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिलेंगे कि उससे आर्थिक वृद्धि को फायदा पहुंचा हो।

एनडीटीवी : यह बात और विवादास्पद हो सकती है जब आप आईएमएफ में हों और साक्षात्कार दे रहे हों।

रघुराम राजन : यह बात विवादास्पद तब और ज़्यादा होती जब आप आईएमएफ में हों और एक सप्ताह पहले ग्लेनईगल संगोष्ठी में समस्त धनी राष्ट्र एकजुट होकर आर्थिक सहायता विषय को आगे बढ़ाने के लिए पंक्तिबद्ध हो रहे थे।

अरविंद सुब्रमणियन : दिलचस्प बात यह है कि ठीक एक सप्ताह पहले, शायद रघु को याद न हो, सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से बताया कि पेपर लिखने में हमारा संयुक्त प्रयास था और बृहतर लेनईगल संगोष्ठी 2005 के आयोजन से ठीक 4 या 5 दिन पहले फाइनेंशियनल टाइम्स के पहले पन्ने पर छपा हुआ था, इस अखबार को वाशिंगटन में हर कोई पढ़ता है, पहले पन्ने पर लिखा हुआ था 'आईएमएफ का कहना है कि आर्थिक सहायता से कोई अंतर नहीं पड़ता है', और शायद रघु को यह याद भी न हो, क्योंकि वह वास्तव में छोड़ चुके थे।

रघुराम राजन : नहीं, मुझे वह घटना याद है।

अरविंद सुब्रमणियन : ये यात्रा पर बाहर थे और प्रबंध निदेशक ने लेखकों को आमंत्रित किया था, लेकिन उनमें से एक उपलब्ध नहीं था, यह उसकी किस्मत थी, इसलिए मुझे ही जाना पड़ा और सारी बातें मुझे झेलनी पड़ीं।

रघुराम राजन : मैं समझता हूँ कि उस दिन अफ्रीकी देशों के तकरीबन 15 वित्त मंत्रियों ने फोन करके मुझसे पूछा होगा कि आखिर आप ये क्या कह रहे हैं ? आप जानते ही हैं कि जो सच्चाई है वह पेपर में बड़ी सावधानीपूर्वक दी गई है, लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि जो बातें सुर्खियों में लिखी गई हैं उन्हें इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने नहीं लिखा है, बल्कि उसे अखबार के किसी सहायक संपादक ने लिखा होगा जो उसे चुटीला बनाकर पेश करना चाहता है।

---

* गवर्नर रघुराम जी. राजन और मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन से बातचीत करते हुए डॉ. प्रणय रॉय - 5 नवंबर 2015 - असंपादित प्रतिलिपि एनडीटीवी

अरविंद सुब्रमणियन : इस बात को प्रणय ज्यादा बेहतर तरीक से जानते होंगे।

एनडीटीवी : जी हां, मैंने हमेशा कहा है कि पत्रकारों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए।

रघुराम राजन : मेरे कहने का मतलब है कि उन सुर्खियों का काफी असर पड़ा, आपको पेपर का निचोड़ पता चल गया, हमने इसे सनसनीखेज खबर के रूप में नहीं लिखा था।

एनडीटीवी : आप दोनों लगभग बर्खास्त किए जाने वाले थे।

रघुराम राजन : आप यह कह सकते हैं कि हमारे बीच बड़े रोचक संवाद हुए थे।

अरविंद सुब्रमणियन : सच तो ये है कि मुझे एक कान्फ्रेंस के लिए बाहर जाना था जहां मैं पूरी अक्लमंदी से यह कहने वाला था कि पेपर में मेरा हाथ नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका, लेकिन हमें आईएमएफ से दूरी बनाए रखनी पड़ी, एक संस्था से लेखक को दूरी बनाए रखना हमेशा बहुत मुश्किल काम होता है। रघु आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री थे, यह कहना बहुत कठिन है कि

रघुराम राजन : लेकिन सच्चाई यह है कि आईएमएफ प्रबंधन ने उस पेपर को समर्थन प्रदान किया, उन्होंने पेपर को देखा था और उनका कहना था कि पेपर सही था, हमें उसके लिए रास्ता ढूंढना चाहिए, वह मुद्दा सही समय पर उठाया गया था।

एनडीटीवी : एक पत्रकार के नज़रिये से बिल्कुल सही समय पर

अरविंद सुब्रमणियन : इसके बारे में सोचे तो अब तक उसे लिखे हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं और पता नहीं हो सकता है कि पेपर का विषय अभी भी ज़िन्दा हो। पता नहीं, लेकिन यह बात पुनः यकीन दिलाने वाली और सुकून बख्शने वाली लगती है कि विश्व बैंक ने विश्व बैंक द्वारा किए गए अनुसंधान के मूल्यांकन के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की है और उस समिति में ऐंगस डियाटन भी थे, जिन्होंने तब यह बात कही थी कि बुनियादी तौर पर आर्थिक सहायता के बारे में लिखा गया सर्वोत्तम पेपर रघु और मेरा था, और वह आज भी अपनी बात पर कायम हैं और इसे वे अपनी कक्षा में पढ़ाते भी हैं, इसलिए पेपर चाहे जैसा भी रहा हो, उन्होंने यह कहकर उसके महत्व की रक्षा की है।

एनडीटीवी : नहीं, नहीं इतना खराब भी नहीं है, लेकिन क्या उस पेपर में आप दोनों किसी एक बात पर सहमत हुए हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जब आप दो अर्थशास्त्री एक साथ हों तो कोई विषय सामान्य रह जाए, आप दोनों के बीसों विचार होंगे और यदि आप बंगाली होते तो 50 विचार होते, कमोबेश आप बंगाली नहीं है।

अरविंद सुब्रमणियन : सच तो यह है कि हम दोनों विश्व के एक ही भाग से संबंध रखते हैं।

एनडीटीवी : बेशक, एक क्षेत्र ऐसा है जिसके बारे में मैं यह नहीं जानता कि कौन कितना विश्वास रखता है, लेकिन उसके संबंध मेरे दिमाग में एक सवाल जरूर है, वह है कि क्या हमारे यहां मुद्रास्फीति या अपस्फीति या फिर अवस्फीति की स्थिति है और इसे परखने के लिए आप कौन से आंकड़ों को देखते हैं।

आइए देखते हैं कि सूचकांकों, थोक मूल्य सूचकांक, तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितनी गड़बड़ है, उनमें कितना नाजुक विचलन है। थोक मूल्य सूचकांक कहता है कि मुद्रास्फीति या अपस्फीति 5 प्रतिशत ऋणात्मक है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उसे 5 प्रतिशत धनात्मक बताता है। अब भारत ही ऐसा देश है जहां दो सूचकांक हैं जो स्थिति को एक-दूसरे से विपरीत बताते हैं जिसमें से एक में (थोमूस डब्लूपीआई) आप विश्वास करते हैं और दूसरे (सीपीआई) में आप। एक अंतिम बात जीडीपी अपस्फीतिकारक के संबंध में जो शून्य तक पहुंचने के आधे रास्ते में है ठीक उसी प्रकार से है जैसेकि उपर्युक्त दोनों स्थितियों का औसत निकाल दिया जाए।

अरविंद सुब्रमणियन : यह तो जोड़-तोड़कर बनाता हुआ, राष्ट्रीय आय लेखा कार्यालय जो प्रक्रिया, संस्था और विश्वसनीय आदि-आदि के बारे में ज़बरदस्त कार्य कर रहा है, उनका काम बहुत ही उच्च स्तरीय है और उसे वे विश्वस्तरीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वे वस्तुतः थोक और उपभोक्ता मूल्यों की माप करते हैं, जीडीपी अपस्फीतिकारक को यूं ही बनाया जाता है, मेरे विचार से पहली बात तो यह है कि यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है और यह पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं है, किंतु जिस मात्रा तक यह अप्रत्याशित होती है उस मात्रा तक पूर्व में कुछ एक अवसरों पर घटित हो चुकी है और जो मेरे विचार से रघु एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए वस्तुतः बड़ी परेशानी पैदा कर देता है, क्योंकि . . . . . .

एनडीटीवी : वे दोनों एकदम अलग-अलग नीतियों का सुझाव देते हैं।

अरविंद सुब्रमणियन : यह बात आपके अभिलेख के लिए है कि ऐसा नहीं है कि मैं डब्लूपीआई और रघु सीपीआई में विश्वास करते हैं। मेरे हिसाब से हम दोनों इस बात में विश्वास करते हैं, यदि मैं कहीं गलत कह रहा हूँ तो रघु मुझे टोकिएगा, कि दोनों ही अर्थव्यवस्था के बारे में सूचनाएं प्रदान करती हैं इसलिए सवाल यह है कि आप इसमें से जितना जरूरी है वह किस प्रकार से लेते हैं और तब प्राप्त हो रही हैरान करने वाली भिन्नतापूर्ण सूचना के मद्देनज़र ब्याज दर और मौद्रिक नीति निर्धारित करते हैं।

एनडीटीवी : आप मुझे एक उदाहरण दें, मान लीजिए कि मुद्रास्फीति की अधिकृत माप सीपीआई है, तब आप इसे लेकर मुद्रास्फीति के बारे में चिंतित होते हैं, तब आप ब्याज-दरों को कम नही करेंगे और यदि आप डब्लूपीआई को अधिकृत माप के रूप में लेते हैं तो भी ब्याज-दर को नहीं घटाएंगे और आप मुद्रास्फीति के बारे में चिंतित नहीं हैं, क्या ये दोनों बाते नीति पर गहरा प्रभाव नहीं डालती हैं ?

रघुराम राजन : हमने कुछ समय पहले सीपीआई को लक्ष्य करना शुरू किया है और मैं समझता हूँ कि शायद लोग भी यही चाहते थे। इस बदलाव का मतलब क्या है ? मेरे विचार से यह बुनियादी तौर पर बास्केट की भिन्नता है। डब्लूपीआई के अंतर्गत बहुत से व्यापार किए जाने वाले माल हैं, वस्तुएं हैं, जिनकी कीमतें घट रही हैं और इसलिए वह नकारात्मक है। सीपीआई के अंतर्गत सेवाएं तथा खाद्यान्न आते हैं, खाद्यान्न पर विश्व के मूल्यों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन सेवाओं का मामला थोड़ा अलग है। भारत में आपको शैक्षिक सेवाएं नहीं मिल सकती है जबकि विदेश में आपको उपलब्ध हैं। भारत में चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं, विदेश में उपलब्ध हैं। इसलिए, भारत में इन सबके मूल्य तेज गति से बढ़ रहे हैं। इस प्रकार मेरे हिसाब से अंतर गैर-व्यापारित वस्तुओं के बीच है जिसका ज्यादातर हिस्सा सीपीआई के अंतर्गत आता है और छोटा-सा हिस्सा डब्लूपीआई के अंतर्गत होता है।

एनडीटीवी : संक्षेप में आपका कहना यह है कि सीपीआई के अंतर्गत 45 प्रतिशत या लगभग 50 प्रतिशत खाद्यान्न मदें, खाद्यान्न एवं पेय-पदार्थ हैं, जबकि थोक मूल्य सूचकांक में 65 प्रतिशत विनिर्मित मदें आती हैं। अर्थात एक उद्योग के बारे में है और दूसरा उपभोक्ता के बारे में है।

रघुराम राजन : बेशक।

एनडीटीवी : एक आखिरी बात, तो फिर हम सीपीआई को क्यों लें जब इसका सरोकार खाद्यान्न से है और भारतीय रिज़र्व बैंक इसके बारे में मानसून की स्थिति को ध्यान में रखने के सिवाय ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है ?

रघुराम राजन : यह केवल खाद्यान्न का मसला नहीं है, यह सेवाओं के बारे में भी है जो हमारे लिए चिंता का विषय था और अभी भी बना हुआ है। लेकिन सोचने की महत्वपूर्ण बात वेतन व मूल्य की मुद्रास्फीति के बारे में है। यदि हम लोगों की इस सोच पर भरोसा करें कि लोग यह महसूस करने लगे हैं कि एक बास्केट भर कर सामान खरीदने पर उसका मूल्य पहले से अधिक बढ़ गया है, तो वे यह चाहेंगे कि उनका वेतन भी बढ़े ताकि वे उतना सामान खरीद सकें।

एनडीटीवी : जी हां।

रघुराम राजन : यह जो दुष्चक्र है वह उन वस्तुओं के बारे में नहीं है जिसे कुछ फर्में खरीदती हैं, बल्कि उन वस्तुओं के बारे में है जिसे आप बाहर जाकर बाज़ार से खरीदते हैं।

एनडीटीवी : बिल्कुल सही।

रघुराम राजन : और यही चीज है जिसे हमें रोकना है, जैसाकि आप जानते हैं कि मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक का फोकस होती है, एक बार, दो बार, ये ऐसा मामला है जिसका सामना मैन्युफैक्चरर्स कर सकते हैं, उनके लिए मुद्रास्फीति का स्तर भिन्न होता है, लेकिन याद रहे कि यह स्तर ऋणात्मक 5 नहीं है जिसके बारे में आपने इशारा किया था, क्योंकि उत्पादन का मूल्य उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा होता या घट रहा होता जितना कि इनपुट के मूल्य जो वस्तुओं से जुड़े होते है और ये मूल्य ज्यादा तेज़ी से गिरते हैं। इस प्रकार से देखें तो सच तो यह है कि उनके लाभ बढ़ रहे होते हैं।

एनडीटीवी : सही है।

रघुराम राजन : इस तरह यदि आप देखें तो वे निवेश करते समय क्या भुनाना चाहते हैं, वह है उन्हें हासिल होने वाला लाभ, और आप जानते ही है यह लाभ डब्लूपीआई की तुलना में सीपीआई में संभवतः थोड़ा अधिक ही मिलता है। इसलिए उसके लिए कोई अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, जहां तक प्रोड्यूसर की बात है उसे निश्चित रूप से उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए।

एनडीटीवी : मेरा मतलब है कि उसे इस बात की चिंता होनी चाहिए कि मांग कम होने के कारण मूल्य कम होते जा रहे हैं ?

रघुराम राजन : बिलकुल।

एनडीटीवी : क्या एक तरह की मंदी की हालत चल रही है, लेकिन क्या यह स्थिति रिज़र्व बैंक के लिए इतनी महत्वपूर्ण है ?

रघुराम राजन : बिलकुल, इसलिए हमें निरंतर सीपीआई पर फोकस करते रहना है, लेकिन हम उस लक्ष्य तक जो हमारे दिमाग में है, कैसे पहुंचेंगे उसमें यदि स्थितियां कमज़ोर रही तो थोड़ा ज़्यादा समय लगा सकता है। इसी प्रकार हम अपनी मुद्रास्फीति प्रक्रियाओं का निर्धारण करते हैं। हमें उस स्थिति से निकलने में एक वर्ष लग गया, प्रारंभिक वर्ष आसानी से बीत गए थे। दो अंकों से आठ तक आने में एक वर्ष, 8 से 6 अंक तक आने में एक और वर्ष और चार अंक तक पहुंचने में एक वर्ष और लग गये, इसलिए हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से प्रयास कर रहें हैं उसका रुख झुकाव की ओर ही होगा।

अरविंद सुब्रमणियन : इस बारे में मैं जिस तरह से सोचता हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि . . . .

एनडीटीवी : जिस तरह से आप असहमत होते हैं ?

अरविंद सुब्रमणियन : जिस तरह मैं मामूली रूप से असहमत होता हूं वह यह है कि . . . .

एनडीटीवी : वस्तुतः आप दोनों की बातचीत मैं आपके कमरे में सुनना चाहता हूँ, वहां आप एक-दूसरे के प्रति बहुत उग्र हो उठते हैं।

अरविंद सुब्रमणियन : जैसाकि आप जानते हैं कि मेरे विचार से पहली बात तो यह है कि उनसे अलग-अलग बातें निकल कर आती हैं और कुछ मामलों में तो उपभोक्ता के लिए कुछ अलग मूल्य होता है और उत्पादक के लिए अलग, यहां तक कि जैसाकि रघु ने कहा

दोनों में तालमेल करना पड़ता है बिलकुल सही बात है। उसका लाभ बढ़ते ही जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसको भी एक चीज का सामना करना पड़ता है जैसे यदि आप इस्पात बेच रहे हों तो आज वास्तविक ब्याज दर बहुत ही ऊंची है, क्योंकि इस्पात का उत्पादन घट गया है और यहां तक कि उसकी डिस्काउंटिंग भी जिसकी वजह यह है कि इनपुट सस्ते हो गए हैं, आपको पता है कि वास्तव में आप उसे चोट पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप बेहतर समझ सकते हैं कि जो मौद्रिक नीति का संचालन करता है वह इन समस्त सूचनाओं को कैसे पचा पाता है और मेरा मानना है कि रघु ठीक कह रहे है, आप सीपीआई के प्रति प्रतिबद्ध हैं, इसे आपको जानना और इसके बारे में सोचना ही चाहिए। और शायद आप जानते ही हैं कि सीपीआई के पक्ष का बचाव मैं किस प्रकार करता हूँ। भले ही प्रणय तुम यह कहो कि बाज़ार में वस्तुओं की मात्रा तो इतनी है, तो फिर आप क्या नियंत्रित करते हो। लेकिन सत्य यह है . . . .

एनडीटीवी : ये सब बातें कृषि पर आधारित हैं ।

अरविंद सुब्रमणियन : यदि कृषि आधारित हैं तो फिर आप उसे बहुत नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच में आप क्या नियंत्रित करते है, आप जानते हैं कि यदि उपभोक्ता उसकी कीमत इस स्तर पर उम्मीद करता है और उनका कहना है कि क्या मैं इस पैसे को वित्तीय क्षेत्र, बैंक या इसी क्षेत्र में ही लगाऊं, इसके लिए वे सीपीआई पर ध्यान देंगे। इस तरह आप ब्याज दरों को एडजस्ट करते हुए उपभोक्ता के निर्णयों को प्रभावित करते हैं और जो मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकती है। यदि वे उस पैसे को बैंक में रखते हैं तो यह अच्छी बात होगी क्योंकि उससे मुद्रास्फीति कम होगी और उनकी बचत ज्यादा होगी। लेकिन हमने जैसाकि आपस में अभी चर्चा की है, उसका आशय मुद्रास्फीति को लक्ष्य करना है, लेकिन यह मुद्रास्फीति का एक लचीला लक्ष्य है, ऐसा नहीं होता है, आप जानते ही हैं कि अमुक समय हमें निश्चित बिंदु तक पहुंचना होता है इसलिए हमें प्राप्त होने वाली अतिरिक्त सूचना से अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ और बातें पता लगती हैं। इस मामले में, जैसाकि आपने कहा कि कुछ अर्थों में अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर है। इसलिए हमें इस अतिरिक्त जानकारी के आधार पर मौद्रिक नीति बनाते समय लचीलेपन का इस्तेमाल करना चाहिए।

एनडीटीवी : तो बात यह है। आप, इनके लिए बहुत सारी बातें ध्यान में रखने के लिए बता रहे है, मान लीजिए कि मंदी की स्थिति है, कोई उद्योग से सामान नहीं खरीद रहा है, कोई कार भी नहीं खरीद रहा है, उत्पादन गिर रहा है और ऐसी स्थिति में आप सीपीआई की ओर देखते हैं और कहते हैं कि मूल्य बहुत अधिक हैं, तो फिर इसके बारे में क्या . . . .

रघुरात राजन : नहीं, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन परिस्थितियों में यदि हम मुद्रास्फीति को कम नहीं कर सकते तब यह वास्तव में मुद्रास्फीति की समस्या बन जाएगी और हमें स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सोचना होगा। कहने का मतलब यह है कि हमने अर्थव्यवस्था की स्थिति को संभलने के लिए थोड़ी सी छूट दे रखी है और यह बिलकुल स्पष्ट है कि ब्याज दर नीति का निर्धारण करते समय हम अर्थव्यवस्था की स्थिति का ध्यान अवश्य रखते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि इतनी सारी सकारात्मकता के बावजूद डब्लूपीआई ऋणात्मक 5 है और उससे आगे .. . . . .

एनडीटीवी : बेशक, यही तो चौंकाने वाली बात है।

रघुराम राजन : हमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना ही होगा क्योंकि आगे चलकर स्थितियां और भी विकट होती जाएंगी। जब विश्व की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ऐसी हालत में अन्य स्थानों पर भी मुद्रास्फीति की स्थिति है। इसे एक अन्य नज़रिये से देख सकते हैं, डब्लूपीआई का मानना है कि विश्व ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर लिया है बल्कि अपस्फीति को ऋणात्मक 5 तक पहुंचा दिया है, ठीक? अब ऐसी स्थिति में हम सीना ठोककर यह नहीं कह सकते कि हमने लक्ष्य पा लिया, ऋणात्मक पांच का लक्ष्य, यह स्थिति हम सभी की वजह से हो पाती, यह स्थिति पूरे विश्व के कारण उत्पन्न होती है, हमारी वजह से क्या होता है वह है छह और सात और वह है सेवाएं, इसलिए मैं यह कहूंगा कि . . . .

एनडीटीवी : क्या आप नहीं मानेंगे कि विश्व ने ऋणात्मक 5 की स्थिति प्राप्त करने में सहायता की है और मानसून ने सीपीआई को धनात्मक 5 तक पहुंचाया है, यदि मानसून खराब होता तो, मेरा कहने का मतलब है....

रघुराम राजन : शायद पिछले कुछ समय से खाद्यान्न की कीमतों ने इसमें योगदान दिया है, लेकिन . . . .

एनडीटीवी : उनका भार लगभग 45 के आसपास है।

रघुराम राजन : भार, लेकिन वे बहुत संतुलित हैं। बहुत-बहुत संतुलित रहे हैं।

अरविंद सुब्रमणियन : मेरे खयाल से विश्व और सरकार दोनों ने मिलकर खाद्यान्न के मूल्य को कम रखने में सहायता की है। मेरे विचार से . . . .

रघुराम राजन : खाद्यान्न की व्यवस्था बहुत ही अच्छी रही है।

अरविंद सुब्रमणियन : इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को छोड़ देना चाहिए . . . .

एनडीटीवी : कुछ चीजों को छोड़कर, हाल ही में मैं एक . . . .

अरविंद सुब्रमणियन : दालें

एनडीटीवी : बिहार में लंबी ट्रिप पर गया था। हर कोई सिर्फ दाल के बारे में बात कर रहा था जो महंगाई की प्रत्याशाओं को प्रभावित कर रही है।

रघुराम राजन : आप सही कह रहे हैं।

एनडीटीवी : आइये देखते हैं कि इस समय महंगाई की प्रत्याशाएं क्या है। इतने सारे प्रयास किए गए हैं लेकिन अभी भी हम महंगाई की हालत को काबू में नहीं कर सके हैं। महंगाई अभी भी बढ़ रही है, क्या ऐसा है, क्या यह दाल का प्रभाव है ?

रघुराम राजन : बिलकुल, अभी तो यही प्रमुख सामान बना हुआ है। जब आप गली में खड़े व्यक्ति से पूछते हैं कि आप महंगाई के बारे में क्या सोचते हैं ? वह आपको एक संख्या बताएगा, जो एक औसत संख्या होगी, जिसे हम महंगाई के संबंध में पिछले पांच वर्ष में भी नहीं छू सके हैं। वह व्यक्ति वही संख्या बताएगा या बताएगी जो उसने पिछली बार खरीद करते समय महसूस की थी जो हो सकती है जैसा कि आपने अभी कहा कि दाल, दूध के बारे में।

अरविंद सुब्रमणियन : प्याज

रघुराम राजन : अण्डे, प्याज। यह अहम चीजे हैं जो लोगों के दिमाग में होती है और वे कहते हैं 'हे भगवान, इनकी कीमतें इतनी बढ़ गईं'। ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि वे उनमें से उसी चीज का दाम बताएं जिनमें अधिक घट-बढ़ हो रही है, उनकी कीमतें बढ़ती हैं फिर घट भी जाती हैं। लेकिन लोग घटी हुई कीमत नहीं बताते हैं बल्कि उन्हें बढ़ी हुई कीमतें याद रहती हैं।

एनडीटीवी : और शायद इसमें मौसम का भी काफी दखल है। मंदी के महीने से लेकर फसल के मौसम तक 20 प्रतिशत का परिवर्तन होता है।

अरविंद सुब्रमणियन : मैं समझता हूँ कि दाल प्रभाव, प्याज के प्रभाव से जुड़ा हुआ है और दोनों में बड़ा रोचक संबंध है और लोगों का इनके बारे में मनोवैज्ञानिक तरीके का रवैया चल रहा है। लेकिन यह मामला डाइवर्जेंस का है, और इतना डाइवर्जेंस क्यों है ? अंततः यदि थोक मूल्य कम हो रहे हैं तो किसी न किसी स्तर पर इसका भी प्रभाव दिखाई देना चाहिए, लेकिन मैनुफैक्चरर्स में इसकी क्षमता नहीं है, उत्पादकों में इतनी सारी शक्तियां नहीं है, सौदेबाजी की शक्ति नहीं है। जिसका अर्थ है कि अंततः उपभोक्ता मूल्य कम होते जाएंगे। इस प्रकार यह कुछ हद तक भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में और थोड़ा-बहुत कृषि के संबंध में बताता है, जैसे सब्जियों और फलों के बारे में हम निश्चित रूप से एकल बाज़ार नहीं हैं, इसकी प्रकार की तटस्थ घट-बढ़ कई चीजों में बड़े स्तर पर पाई जाती है, इसलिए इन चीजों की एक स्थान पर किल्लत होने से उसका प्रभाव दूसरे स्थान पर पड़ता है और वहां हालात खराब होने लगते हैं, जिसका हमें समाधान प्रस्तुत करना होगा। मेरे विचार से दाल-प्रभाव दीर्घकालिक कृषि नीति से जुड़ा हुआ है और आप जानते हैं कि हम उसका समाधान कैसे कर रहे हैं . . . .

एनडीटीवी : सच तो यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हर साल कोई न कोई चीज उभर कर आ जाती है, प्याज, दाल, हो सकता है टमाटर या कोई भी चीज़, और हम उसे नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर होने लगती है तब हमें आयात करने में लंबा समय लग जाता है, ऐसी स्थिति में क्या हम पहले से ही इसके लिए कोई योजना नहीं बना सकते ?

रघुराम राजन : मेरा मानना है कि खाद्यान्न व्यवस्था बेहतर है, उनमें से एक चीज जिसे नियंत्रित किया गया है वह है अनाज। मेरे कहने का मतलब है चावल, गेहूं और वह भी आंशिक रूप से क्योंकि . . . .

एनडीटीवी : बफर स्टॉक की वजह से।

रघुराम राजन : क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्यों में धीमापन आया है। साथ ही, विश्व में मूल्य अपेक्षाकृत कम रहे हैं, हम आयात कर सकते हैं, किंतु इसे नियंत्रित करना ज़रूरी है, क्योंकि हम ज्यादातर इन्हीं चीजों की खरीद करते हैं। इसलिए जब किसान सोचता है कि क्या चीज उगाई जाए तब वह तय करता है कि अमुक चीज उगाए ताकि फायदा ही फायदा हो।

एनडीटीवी : जी सर

रघुराम राजन : मैं इसे उगा सकता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर सरकार को बेच सकता हूँ। किंतु अन्य चीजों के लिए हम मूल्य का निर्धारण करते हैं लेकिन उसे बहुत अधिक खरीदते नहीं हैं और इसकी वजह से हमारो ज्यादातर ध्यान इसी की और रहता है और सत्य यह है कि इन चीजों को हम भारी मात्रा में पैदा करते हैं जो हमारे भारी-भरकम बफर-स्टॉक के रूप में दिखाई देता है।

एनडीटीवी : जी हां, मेरा मतलब है अनावश्यक रूप से इतना अधिक बफर-स्टाक जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है ।

रघुराम राजन : हम . . . . . की ओर बढ़ते जा रहे हैं।

एनडीटीवी : मुझे प्रभावित करती है, चूंकि इसकी पैदावार अनिश्चित है इसलिए फसल के पैटर्न को प्रभावित करता है, गेहूं बोया जाए या चावल।

रघुरात राजन : बिलकुल सही, और इन चीजों को संतुलित रखते हुए, लेकिन दालों की कीमतें बढ़ाकर आप किसानों को प्रोत्साहित कर रहे होते हैं कि वे इसकी फसल पैदा करने की ओर उन्मुख हों, जिसकी वास्तव में दीर्घकाल में हमें ज़रूरत है, बल्कि बाज़ार की शक्तियों को कार्य करने की आवश्यकता है कि लोगों को क्या चाहिए, उन्हें वही पैदा करना चाहिए।

एनडीटीवी : जी हां।

रघुराम राजन : ऐसा करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को उस स्तर पर रखना होगा जो बाज़ार मूल्य से नीचे हो। वे वस्तुतः समर्थन-मूल्य हैं न कि बाजार मूल्य, जो कुछ लोगों के लिए बाज़ार मूल्य बन जाते हैं।

एनडीटीवी : इसे अन्य वस्तुओं तक लागू करने के लिए किस बात को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है।

अरविंद सुब्रमणियन : जी हां, मेरे विचार से जैसा हम कृषि के बारे में सोचते हैं या जैसाकि आप जानते हैं, इसमें दो प्रकार के नीतिगत मुद्दे निहित है। मेरे विचार से फसल का पैटर्न, अनाज बनाम प्रोटीन, और याद रहे अंगुस डेयटन ने उमदा शोध किया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत में आय का स्तर बढ़ा है इसलिए प्रोटीन की मांग बढ़ गई है और हम उतना अनाज नहीं खा रहे हैं जितना खाना चाहिए, यदि हम फसल उगाने का ऐतिहासिक पैटर्न अपना रहे होते तो। इसलिए, प्रोटीन, तथा शाकाहारी के लिए दाल कमज़ोर आहत बन गई है अतः हमें उसके अनुसार योजना बनानी चाहिए।

एनडीटीवी : जी हां।

अरविंद सुब्रमणियन : इसलिए दालों की समस्या उसके मूल्यों, प्रौद्योगिकी आदि-आदि को लेकर है। लेकिन हमारे पास फल और सब्ज़ियों की भी समस्या है, जो थोड़ा अलग प्रकार की समस्या है। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि दीर्घकाल के लिए इसकी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए हमें भारत को कॉमन मार्केट बनाना होगा, क्योंकि कुछ ही राज्य में इनकी पैदावार होती है लेकिन प्रतिबंध के कारण वहां से दूसरे स्थान नहीं जा पाती हैं। मेरी समझ से ऐसी चीजें बाज़ार में समय से नहीं पहुंचती हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ जैसाकि मैंने आर्थिक सर्वेक्षण में कहा है कि कृषि में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि 5000 देश और 5000 कृषि बाज़ार हैं।

एनडीटीवी : क्या मैं आप दोनों से एक बात पूछ सकता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। किसी एक चीज की कीमत इतना ज्यादा कैसे बढ़ जाती है, यह एक अजीब बात है, क्या ऐसा जमाख़ोरी करने वालों की वजह से होता है, मेरा मतलब है कि इसका आरोप इनपर लगना चाहिए। यह हमारी गलती है, बल्कि क्या हम एकबारगी यह कह सकते हैं कि ये बकवास है।

रघुराम राजन : मेरे हिसाब से इसके लिए सरकार जवाबदेह हैं।

एनडीटीवी : यही उस प्रश्न का जवाब है।

अरविंद सुब्रमणियन : नहीं, मेरे विचार से . . . . .

एनडीटीवी : एक अर्थशास्त्री के नज़रिये से

अरविंद सुब्रमणियन : एक अर्थशास्त्री की दृष्टि से इसमें समझने की यह बात है कि ऐसा क्यों होता है . . .

एनडीटीवी : आरोप किसी और पर कैसे लगा दिया जाए।

अरविंद सुब्रमणियन: नहीं, नहीं, यह तो देखने का एक दृष्टिकोण है। मेरे विचार से यह देखने की ज़रुरत है कि कीमतों की जो सूचना फैलती है उससे क्या पता चलता है।

एनडीटीवी : बिलकुल

अरविंद सुब्रमणियन : और यदि उनसे यह पता चलता है कि चीजों की किल्लत है तब इसका अर्थ वास्तव में है। इस समस्या को देखने के अलग तरीके भी हैं। मेरे ख़याल से इस समस्या के दीर्घकालिक प्रभाव को भी ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए।

एनडीटीवी : ये आपने बहुत सही बात कही है। ओके, क्या मुद्रास्फीति के बारे में किसी को कोई प्रश्न करना है ? कोई ऐसा जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स से हो और बंगाली हो, उसे सवाल पूछने का मौका पहले दिया जाएगा। कोई? शायद मुद्रास्फीति पर और कोई प्रश्न नहीं है ? आप जानते हैं कि ये सब मूल्यवृद्धि के मारे हुए नहीं है, बल्कि . . . .

रघुराम राजन : ये बात अब इतिहास हो चुकी है, इतिहास। अब मुद्रास्फीति की समस्या क्यों रहनी चाहिए।

एनडीटीवी : कोई सवाल पूछना चाह रहा है, हां पूछिए

अरविंद सुब्रमणियन : थोड़ा तेज़ आवाज में बोलें

विद्यार्थी 1 : यह सभी जानते हैं कि मुद्रास्फीति अब नियंत्रण में है, लेकिन क्या यह कायम रखने योग्य है कि एक और दर में कटौती की जरूरत पड़े, जो शीघ्र ही कभी भी की जा सकती है ?

रघुराम राजन : तो यह बताने का इनडायरेक्ट तरीका है, आप पूछना चाहते हैं कि क्या हम दरों में कटौती करने जा रहे हैं ?

एनडीटीवी : मैं उतना भी मूर्ख नहीं हूँ जितना कि दिखाई दे रहा हूँ ।

रघुराम राजन : हमने अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में सारी बातें बताई हैं, हमने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है और समस्त कारकों का लाभ उठाया है। जब तक कि और कोई गुंजाइश नहीं बनती है और हमारी उसपर निर्भरता है, तब तक हम वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं।

अरविंद सुब्रमणियन :दरअसल, मुझे रघु को याद दिलाना पड़ेगा, कि वह स्वयं की मौद्रिक नीति वक्तव्य को भूल बैठे हैं। और मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने स्वयं कहा था कि आगे चलकर मौद्रिक नीति का रुख समंजनकारी होगा। किस प्रकार की, आपके प्रश्न के अनुकूल जो आपने पूछा है, वह जो कह रहे हैं उसके बारे में वे बिलकुल खुलापन रखते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आरबीआई और भी अधिक के लिए मौजूद है, वह बंद नहीं है, किसी भी अच्छी स्थिति या अल्पकाल के लिए । और अधिक ब्याज दर कटौती हो सकती है, लेकिन उन्होंने स्वयं को खुला रखा है, जैसे ही मूल्यों के बारे में और डाटा आएंगे, आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुरूप वे उसपर विचार करेंगे, लेकिन वे बुनियादी तौर पर समंजनकारी हैं, शायद आपको याद होगा, रघु . . . .

एनडीटीवी : समंजनकारी

रघुराम राजन : मैं समंजनकारी शब्द से सहमत हूँ।

एनडीटीवी : मेरा एक सुझाव है, हम लोग भी कुछ ऐसा करते हैं कि काफी सैंपलिंग का कार्य करते हैं और विभिन्न स्थानों से सैंपल इकट्ठा करते हैं और फिर उसमें थोड़ी सी इकॉनॉमेट्रिक्स लगाते हैं, आप भी दोनों सूचकांकों को बड़े सैंपल में जोड़ सकते हैं, इस प्रकार उनके भारांक स्वतः समायोजित हो जाएंगे, और आपको खाद्यान्न तथा मैनुफैक्चर दोनों प्राप्त हो जाएंगे। अतः यदि आप सीपीआई और डब्लूपीआई दोनों मिला देते हैं तो आप को मुद्रास्फीति की एक बेहतर तसबीर मिल सकती है।

रघुराम राजन : हो सकता है, लेकिन यह याद रखना होगा कि सीपीआई इस बात पर आधारित है कि उपभोक्ता क्या खरीदता है, ठीक ? इसलिए यदि आप वास्तव में उपभोक्ता का भला चाहते हैं, और उसके निवेश संबंधी निर्णय या उपभोग के निर्णय के प्रति चिंतित हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि आपको शायद सीपीआई की ओर देखना होगा, बजाय मध्य मूल्यों के।

एनडीटीवी : एक अन्य क्षेत्र चिंता का कारण बना हुआ है, उद्योग बहुत खराब हालत में है। वे कुछ चीजों के बारे में मांग कर रहे हैं, वे काम नहीं दे रहे हैं और यह सुनना वास्तव में आश्चर्यजनक लगता है कि राजनेता यह कहते हैं कि आगे बढ़ो, कुछ करो। 'उद्योगपतियों अपनी इज्ज़त बचाओ'। ऐसे काम नहीं होता है, उन्हें सिग्नल चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन चाहिए और वे कुछ भी करने के लिए एकदम तैयार है। इसकी कुछ समस्या तो यह है कि संकट के बाद से विश्व अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई है। विश्व अर्थ व्यवस्था की वृद्धि 2.5 प्रतिशत की दर से हो रही है जो बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए हमारा निर्यात घट रहा है। आइये हम इस समय हमारे निर्यात की स्थिति पर एक नज़र डालते हैं। महीना-दर-महीना निर्यात ऋणात्मक होता जा रहा है। सितंबर में वह 24 प्रतिशत था, और मेरा अंदाज़ा है कि इस बारे में आप दोनों के मत थोड़े भिन्न होंगे, यह विनिमय दर आखिर क्या है ? क्या रुपया बहुत ऊंचा चढ़ गया है ? आइये देखते हैं कि डालर के मुकाबले रुपया कैसे गिरा है, लेकिन यहां महत्वपूर्ण यह है कि क्या रुपया अन्य उभरते बाज़ारों की तुलना में भी गिरा है ? ये सामने देखिए। दक्षिण अफ्रीका की तुलना में रुपया 30 प्रतिशत ऊपर गया है, ब्राज़ील के मुकाबले 36 प्रतिशत ऊपर गया है और रूस की तुलना में 49 प्रतिशत ऊपर गया है। आप इंडोनेशिया की तुलना में स्पर्धा कैसे करेंगे जहां रुपया 7 प्रतिशत ऊपर गया है, तुर्की की तुलना में 19 प्रतिशत तथा मेक्सिको की तुलना में 13 प्रतिशत ज्यादा ऊपर गया है। क्या रुपए का मूल्य नीचे रहना चाहिए ? मैं अवमूल्यन जैसे शब्द के इस्तेमाल से नफरत करता हूँ जो विगत के हैंग ओवर की तरह है, एक बुरा शब्द जो हमें और भी प्रतिस्पर्धी बनाता है।

अरविंद सुब्रमणियन : क्या हम पिछले चार्ट पर वापस जा सकते हैं।

एनडीटीवी : जी हां, आप देख सकते हैं कि निर्यात घट रहा है।

अरविंद सुब्रमणियन : मेरे विचार से प्रणयने जो सनसनीखेज़ हेडलाइन यहां प्रस्तुत की है और जो वास्तविकता है, वह यहां के श्रोतागण के लिए महत्वपूर्ण है।

एनडीटीवी : उन्होंने आपको क्या दिया, आर्थिक सहायता से काम नही चलता है : निर्यात घट रहा है।

अरविंद सुब्रमणियन : सही है, यदि आप इसे देखें तो वास्तव में यह स्थिति भयावह, तबाही वाली दिखाई देती है, लेकिन उनमें दो बातों की दुरुस्तगी की ज़रूरत है, पहली बात यह है यह समग्र निर्यात है और आप जानते हैं कि हम तेल संबंधी अनेक उत्पादों का निर्यात भी करते हैं। इसलिए सच्चाई यह है कि तेल की कीमतें कम हुई हैं जिसका फायदा हमें मिला है।

एनडीटीवी : हम प्रायः यह कहते हैं कि हमारा अवमूल्यन नहीं हो सकता क्योंकि हम कितना ज्यादा तेल आयात करते हैं, अब हम तेल का निर्यात करने लगे हैं।

अरविंद सुब्रमणियन : नहीं, मैं यह कहना चाहता हूँ कि तेल से इतर चीजों का निर्यात क्योंकि उससे हमें फायदा मिल रहा है, इसमें जो दिया गया है उससे कहीं अधिक तेल की कीमतें कम हो गई हैं।

एनडीटीवी : ओके

अरविंद सुब्रमणियन : यह बहुत बड़ा सुधार हुआ है। दूसरी याद रखने योग्य बात यह है कि, जैसाकि रघुने पहले कहा था कि विश्व में कीमतें तेज़ी से घट रही हैं। इसलिए यदि आप जो कह रहे हैं, वस्तुतः तेल से इतर आयात का मूल्य नहीं है, बल्कि यह देखना चाहिए कि कितनी कारे, कितने टन इस्पात, कितना एल्युमिनियम बाहर जा रहा ये सब एकदम भिन्न है। अतः निर्यात का सही आकलन आप जो दिखा रहे हैं काफी कम निषेधकारी है। इसलिए यह उस अर्थशास्त्र से थोड़ा ही कम है जितना कि उसकी कीमत है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था अभी भी नकारात्मक स्थिति में है जो निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रही है। इसलिए जहां तक इस समस्या का प्रश्न है हमें यह समझना होगा कि कितना हमारे नियंत्रण से बाहर है और कितना नियंत्रणाधीन है, और तब हमें सोचना होगा कि हमारे पास कौन से उपकरण हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे पास अनेक उपकरण हैं। उसमें से एक यह है कि प्रधानमंत्री की 'भारत में निर्मित' की मुहिम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि सबसे अहम बात यह है कि हम किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को मध्य अवधि से दीर्घकाल में प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं, क्योंकि वही चीज सिद्धांततः हमारे निर्यात को आगे बढ़ायेगी। यह हुई मध्यावधि की बात, और आगे की बात परजो में आने जा रहा हूँ वह है घुटने की तकलीफ, अल्पकालिक प्रतिक्रिया, अरे, कुछ विशिष्ट निर्यातकों को सहूलियत दी जाए, इस्पात के लोग बेहाल हैं उन्हें सब्सिडी दे दी जाए या उन्हें थोड़ा संरक्षण दे दिया जाए और मेरे विचार से यहां हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। हमें संरक्षण प्रदान करके संभावित फायदे देने एवं उसकी लागत के बीच संतुलन रखना होगा।

रघुराम राजन : लागत होगी, आपके पास ऐसा उद्योग है जिसमें उस वस्तु को इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, टैरिफ बढ़ा दीजिए और तब आपकी कार का निर्यात गिर जाएगा क्योंकि अब कार निर्यातकों के लिए इस्पात महंगा हो गया है, इस प्रकार दोनों में संतुलन कायम हो जाएगा।

एनडीटीवी : व्यक्तियों को लक्ष्य करना क्या थोड़ा-बहुत बाज़ार के साथ हस्तक्षेप करना नहीं है।

अरविंद सुब्रमणियन : यह भी विवेकपूर्ण हो गया है और हम सभी जानते है कि इन्हीं चीजों से सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन तब हमारे पास एक तीसरा उपकरण है विनिमय-दर का और मेरे ख़याल से हमें यथासंभव प्रतिस्पर्धी विनिमय-दर रखनी चाहिए, यही अनुभव चीन तथा पूर्वी एशियाई देशों से हमें प्राप्त होता है।

एनडीटीवी : प्रतिस्पर्धी विनिमय-दर, कहने का मतलब है कि हमारी विनिमय-दर अन्य कई उभरते बाज़ारों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी होती जा रही है। यदि आप समस्त उभरते बाज़ारों के सूचकांकों को देखें तो पाएंगे कि हमारी विनिमय-दर अधिक से अधिक गैर-प्रतिस्पर्धी होती जा रही है। मैं जानता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से इसे हां कहना मुश्किल होगा, रुपए को 70-75-80 तक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा सुनना भयावह लगता है, लेकिन यदि यह दर अन्य उभरते बाज़ारों के अनुरूप है तो फिर हमें भी वही क्यों नहीं करना चहिए जो हमारे लिए सबसे बेहतर है ?

अरविंद सुब्रमणियन : प्रणय, इस बारे में रघु जवाब देंगे, लेकिन मेरा मानना है कि एक ओर तो हमें प्रतिस्पर्धी विनिमय-दर बनाकर रखनी होगी, लेकिन आप उस विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष इसे कैसे रख पाएंगे जिसका हम एक हिस्सा हैं और इनफ्लो का क्या जो हमें प्राप्त हो रहे है ? यदि हम किसी जादू से आने वाले समय में धीरे-धीरे प्रतिस्पर्धी हो पाते और धीरे-धीरे विनिमय दर में वृद्धि होती तो बहुत ही अच्छा होता, यदि बाज़ार में अचानक ऐसा कहा जाने लगे कि हे भगवान ये अर्थव्यवस्था तो ऐसी है जिसमें विनिमय-दर नीचे जा रही है, तब ये सारी समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, इस संत्रास से बाहर निकलने के लिए हमें परिवर्तनकारी विनिमय-दर की घट-बढ़ प्राप्त होगी जो बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाली होगी और तब आपको संतुलन लाना होगा।

एनडीटीवी : क्या हम निचली लाइन से कोशिश कर सकते हैं और अपने स्पर्धियों से स्पर्धा कर सकते हैं ?

रघुराम राजन : लेकिन मेरे ख़याल से पहली बात तो यह है कि ये संख्याएं कुछ हद तक गुमराह करनेवाली हैं। मैं आपके मतभेदों को मानता हूँ लेकिन याद रहे कि रुस में मुद्रास्फीति की गंभीर समस्या है क्योंकि करेंसी का मूल्यऱ्ह्रास बहुत ज्यादा हुआ है। इसी तरह ब्राज़ील उच्च स्तर की मुद्रास्फीति को रोकने में लगा हुआ है, हालांकि उन्होंने यह शुरुआत हमसे कहीं कम दर पर ही कर दी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, किसी भी प्रतिस्पर्धी लाभ को असमायोजित किया जा रहा है और यही वह बिंदु है जिसे नोट किया जाना चाहिए कि एक औद्योगिक राष्ट्र, क्योंकि उनके केंद्रीय बैंकों की साख है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था में इतना अधिक तोड़-मरोड़ नहीं है, अपनी करेंसी के

मूल्य को घटा सकते हैं और उसका प्रतिस्पर्धा में फायदा उठा सकते हैं, जो महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से यूरो क्षेत्र एक ऐसा उदाहरण है जहां वे बेहतर कर रहे हैं क्योंकि यूरो की कीमत घट गई है, लेकिन उभरते बाज़ारों के लिए हमेशा यह जोखिम होता है कि जब भी अल्पकाल में आपको कोई फायदा होता है वह मध्यावधि में ज्यादा महंगाई के कारण चला जाता है, जो उन समस्त प्रयासों को धो देता है जो अब तक आपने किए हैं। इस तरह का मामला इटली में हुआ था, इटली में इस प्रकार का इतिहास रहा है जब उसके लीडर इस तरह मूल्यऱ्हास किया करते थे, उसका छह महीने तक फायदा उठाते थे और होता यह था कि महंगाई आती थी जो फायदे का सफाया कर देती थी, इसलिए उन्हें लगातार मूल्यऱ्हास करना पड़ा था। अब सवाल यह है कि आप किसे वरीयता देंगे, मध्यावधि और दीर्घावधि में महंगाई बनी रहने देंगे या अपने अन्य समस्त साधनों के माध्यम से रोकना चाहेंगे और अपने साधनों के हाथों मजबूर हो जाएंगे जैसाकि अरविंद ने अभी बताया है कि आपको सुधार लाना है 'भारत में निर्माण' की क्षमता को बढ़ाने के माध्यम से, अपने कारोबारी विनियमन को बेहतर बनाकर ?

एनडीटीवी : लेकिन आप जानते ही हैं कि किसीने यह कहा है कि दीर्घकाल में हम सब नहीं रहेंगे, लेकिन आपने जो बात कही है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन मूल्यऱ्हास की स्थिति काफी खराब है और ऱ्हास बहुत तेज हो रहा है। आप एक पेशेवर की तरह इसे समय रहते धीरे-धीरे नियंत्रित कर सकते हैं। क्या हम इसे मात्र अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखते हुए धीरे-धीरे नियंत्रित करेंगे ?

रघुराम राजन : मेरे ख़याल से प्रतिस्पर्धा के मामले में एक बात और है जिसका यहां उल्लेख नहीं हुआ है, वह है उत्पादकता में वृद्धि, इसलिए जब तक उत्पादकता में वृद्धि सुदृढ़ है तब तक हम सामान्य विनिमय-दर रख सकते हैं, जो वैसे भी अन्यथा मूल्य से अधिक मूल्य पर आंकी जाएगी, लेकिन सारी चीजों को मिलाकर। यहां अरविंद के दूसरे बिंदु पर ध्यान देना होगा कि जब आप निर्यात की मात्रा को देखते हैं, तो पता लगता है कि निर्यात बहुत अधिक नहीं घटा है और इसकी तुलना इस प्रकार से की जा रही है जैसे हर कोई निर्यात की वजह से परेशान है। तुलना से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग बाहर के हैं, इसलिए बृहत् अर्थों में हम प्रतिस्पर्धा बनाए हुए हैं।

एनडीटीवी : तो आपका कहना है कि इस समय जो विनिमय-दर है वह बिलकुल ठीक है ?

रघुराम राजन : मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ कि जिस दर पर विनिमय-दर है वह एकदम दुरुस्त है।

अरविंद सुब्रमणियन : या इसे दूसरी तरह भी कह सकते है कि यदि आप किसी उद्योगपति से पूछे कि सर्वोत्तम विनिमय-दर का स्तर क्या होगा, वह हमेशा कहेगा कि वर्तमान स्तर से 20 प्रतिशत कम दर पर, क्योंकि वह हमेशा तुलना करके ही बताएगा। लेकिन मेरे विचार से इन तमाम चर्चाओं में एक चीज़ गायब है, वह है माइक्रो-आर्थिक मुद्दा जो पूरे भारत में समस्त स्तरों पर बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, शायद आपके स्तर पर नहीं, जब आप इसके नियंत्रण की बात कर रहे थे और आप चाहते है वहां उसे कैसे किया जाए, यहां इसे सबसे ज्यादा दुश्वार जो चीज़ बनानी है वह यह है कि हम पूंजी के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा खुले हैं। यदि पूंजी भारी मात्रा में आने लगे तो रघु को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ? क्योंकि जब पूंजी आती है तब चीजों पर दबाव ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगता है, और हमारी प्रणाली हमेशा से सभी समय समस्त रूप में विदेश से आने वाली पूंजी की अपेक्षा रखती रही है, जो असंदिग्ध सच्चाई है। लेकिन मेरे विचार कहीं गहरे मन में यह तनाव मौजूद है कि हम उतनी मात्रा में पूंजी हासिल कर लें जितनी की हमें ज़रूरत है लेकिन जितनी अधिक पूंजी आएगी उतनी ही ज्यादा बाहर जाएगी।

रघुराम राजन : इस विषय पर हम दोनों ने मिलकर एक अन्य पेपर भी लिखा था।

अरविंद सुब्रमणियन : ये आसान नहीं है इसलिए हमें उक्त बातों को भूलना नहीं चाहिए।

एनडीटीवी : मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ब्याज-दर या विनिमय-दर के बारे में आपसे थोड़ा समंजनकारी रवैया चाहते हैं।

अरविंद सुब्रमणियन : निश्चित रूप से आप सभी जानते ही हैं कि ब्याज-दर और विनिमय-दर आपस में जुड़ी हुई हैं

एनडीटीवी : जी हां, मैंने चीन के बारे में रिपोर्टिंग की थी, चूंकि वे ट्यूनिक्स पहनते हैं और उनकी फैक्टरियां रूस की फैक्टरियां जैसी हैं, मैं उनकी फिल्में बनाया करता था। तब मैंने पहला गोल्फ-कोर्स, पहला मैकडोनल्ड्स देखा था जो बहुत ही बड़ा था, और सड़क के सामने बृहत आकार की डेंग जियोपिंग उसे आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में बनी थी जो मेरे कैमरे की तसवीरों का एक हिस्सा थी। और मैं इस बात पर निगाह रखता था कि कितनी विदेशी पूंजी आ रही थी। उन दिनों 80 बिलियन, 100 बिलियन डालर प्रति वर्ष आती थी। हमारी स्थिति उनके आसपास भी नहीं थी, और कई लोगों का कहना है कि अब तो उसमें सकल मात्रा से 2-3 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है।

अरविंद सुब्रमणियन : मैं आपको बताता हूँ . . . . .

रघुराम राजन : हम ऐसी बात शायद नहीं कहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से वे विदेशी पूंजी ले रहे थे उसी प्रकार से वापस भी कर रहे थे, उन्होंने 4 ट्रिलियन डालर की मालियत की आरक्षित निधि बना ली थी, जिसपर अर्जन बहुत ही कम था, तो यह स्थिति थी चीन की, बेचारे चीनी परिवार के लोग, औद्योगिक राष्ट्रों के बदले में वे आस्तियां खड़ी कर रहे थे। अब, वह कितनी है, चलिए बेशी बचत की बात ले लीजिए ? इसने उनके दीर्घकालिक उपभोग की संभावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अब चीन बड़े रोचक तरीके से महत्वपूर्ण अंदाज में आगे बढ़ रहा है और अपनी घरेलू खपत को बढ़ा रहा है।

एनडीटीवी : बिलकुल सही।

रघुराम राजन : क्योंकि उसने इस तरीके को ज्यादा स्थायित्व बनाए रखने वाले तरीके के रूप में प्रयोग किया था . . . .

अरविंद सुब्रमणियन : निःसंदेह, लेकिन आपने वह बात नहीं कही जिसकी मैं अपेक्षा कर रहा था, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब आप . . . .

एनडीटीवी : वे इस बात पर खुश दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने वह बात नहीं कही जो आप सुनना चाह रहे थे।

अरविंद सुब्रमणियन : आप जानते हैं कि रघुने जो बात बताई है, 80 बिलियन डालर आने से उसने सभी चीजों पर प्रभाव डाला, ऐसा पिछले दस वर्ष में घटित हुआ है, लेकिन यदि आप 1979 में जाकर देखें तो जिस प्रकार की पूंजी चीन को हासिल हुई थी वह कोई मज़ाक नहीं था, वह सट्टाग्रस्त पूंजी थी, जो फैक्टरियों में प्रमुख धन के रूप में निवेश की गई थी . . . .

एनडीटीवी : कोका कोला फैक्टरी और इसी तरह की अन्य . . . .

अरविंद सुब्रमणियन : जी हां, एफडीआई के बारे में आप जानते ही होंगे, एफडीआई अच्छी चीज है। यहां हम जो बात कर रहे हैं वह अन्य चीजों के बारे में है, ये उस उधार के बारे में है जो हम विदेशी करेंसी में लेते हैं, आज जानते हैं कि सट्टेबाजी वाली पूंजी जो आती है, हमें इसके प्रति अत्यधिक सावधान रहने की ज़रूरत है और आज भी चीन इस बात की इजाज़त नहीं देगा। मेरे विचार से इन चीजों की अनुमति देकर हम चीन से ज्यादा खुले हुए हैं।

रघुराम राजन : यह एक ऐसी बात है जहां आप और मैं मेरे विचार से थोड़ा भिन्न मत रखते हैं। मैं इस बात से ज्यादा इत्तेफाक़ रखता हूं कि विदेशी पूंजी फायदेमंद होती है। ऐसा, खासतौर से भारत में है, जहां जोखिम-पूंजी मुश्किल से होगी, और इस तरह बहुत ही ज्यादा धन इन वर्षों में स्टॉक मार्केट में चला गया है। निश्चित ही वे चाहेंगे कि उस पर उनकी कमाई हो, और होना भी चाहिए। लेकिन उससे इक्विटी-बफर भी उपलब्ध हो रहा है जिसकी हमें हमारी कंपनियों के लिए सख्त ज़रूरत थी, प्रायः आप यदि भारतीय स्रोतों की ओर देखेंगे तो पाएंगे कि जोखिम पूंजी बड़ी मुश्किल से मिलेगी। अधिकांश भारतीय स्रोत कर्ज चाहते हैं, और मेरे विचार से यहां वे बहुत कीमती भूमिका अदा कर रहे हैं, निजी इक्विटी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं, यह मात्र टी आई नहीं है बल्कि अन्य प्रकार की . . . .

अरविंद सुब्रमणियन : लेकिन, मेरे विचार से विनिमय-दर को मात्र पूरा करने के लिए, किंतु रघु को भी याद होगा, कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के समाप्त होते हुए वर्ष में तेजी पैदा हो गई थी, अनेक इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों ने विदेशी मुद्रा में उधार ले लिए थे, उन्होंने डालर-ऋण लिया था, जिसके संबंध में हम दोनों इस बात से सहमत थे कि पूंजी के जितने भी स्वरूप थे उसमें यह सबसे घातक था। उन्हें उधार मिल रहा था, इसलिए उन्होंने डालर में उधार ले लिया, वे पावर और सब कुल बेच रहे थे। जब विनिमय-दर कम हो गई तब उनके उधार की लागत एकदम से बढ़ गई, बेतहाशा . . . .

एनडीटीवी : और बहुत सी कंपनियां इसका शिकार हो गईं . . . .

अरविंद सुब्रमणियन : बेशक । यहां तक कि उसका असर आज भी महसूस किया जा रहा है, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, कि हम किस प्रकार की विदेशी पूंजी प्राप्त कर रहे हैं . . . .

एनडीटीवी : लेकिन आप दोनों सहमत होंगे कि फैक्ट्रियों में आस्ति उत्पन्न करने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्पष्ट रूप से अच्छा था और हमारी आस्ति करीब 30, 40 बिलियन थी और चीन में यह स्थिति 20 साल पहले 80 बिलियन थी। इसलिए आज हमें उसे 30, 40 बिलियन से बढ़ाकर 100 बिलियन करने का प्रयास करना चाहिए।

अरविंद सुब्रमणियन : निःसंदेह ।

एनडीटीवी : एफडीआई में

अरविंद सुब्रमणियन : एफडीआई में, बिलकुल ।

एनडीटीवी : विनिमय-दर के बारे में निकोलस जेम्स, सेंट स्टीफन ने सवाल उठाए हैं।

अरविंद सुब्रमणियन : लाल सितारा जीतेगा।--

एनडीटीवी : अच्छा

विद्यार्थी 2 : मेरा आपसे सवाल यह है कि आज अमरीका की ट्रेजरी द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बहुत सा कर्ज़ दिया गया है, जो ट्रिलियन डालर होगा, और चीन के पास उसका 20 प्रतिशत है। लेकिन, लोग

यह जानते हैं कि उन्होंने जितना प्रिंट कर दिया है, उससे पीछे नहीं जा सकते और वे अभी भी प्रिंट करते जा रहे हैं, ठीक ? इसलिए आज जिनके पास डालर नोट है, यदि वे उनके पास जाकर कहें कि इसे वापस ले लो, तो मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति, यहां तक कि 100 प्रतिशत लोग यही कहेंगे कि वे उसके आधे को भी बैक-अप नहीं करेंगे, इसलिए आपसे मेरा सवाल यह है कि जहां इतने सारे बाजार उभर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतने सारे खिलाड़ी हैं, क्या हम अंतरराष्ट्रीय मानक के रूप में डालर से हटकर एक जबरदस्त परिवर्तन देख सकेंगे, हो सकता है किसी अन्य करेंसी की ओर, जो बड़े निर्यातक हो सकते हैं और वास्तव में वे अपने कर्ज को बैंक-अप कर सकेंगे।

रघुराम राजन : आप कुछ दर्शन संबंधी प्रश्न पूछ रहे हैं, कर्ज को समर्थन देने का क्या अर्थ है। मेरा मतलब है कि तकनीकी रूप से वे डालर प्रिंट कर सकते हैं, फेडरल रिज़र्व के पास प्रिंटिंग प्रेस है और वे कर्ज को चुकाने के लिए जितना चाहे उतना डालर प्रिंट कर सकते हैं और वह वैध मुद्रा होगी। क्योंकि वे चुकौती कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं आपको वापस डालर दूंगा, क्योंकि वे यूरो या रुपया नहीं जारी करते है। इसलिए उस राष्ट्र की वैल्यू यह है कि उसके पास रिज़र्व है, और यह वैल्यू भी हमारे पास है, क्योंकि हम रुपए में ऋण जारी कर सकते हैं और यदि किसी को चाहिए हम रुपए प्रिंट करके उन्हें दे सकते हैं। आप जो प्रश्न कर रहे हैं वह यह है कि क्या लोगों को यह विश्वास है उनके कर्ज ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगे। क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं हैं, उल्लिखित संसाधन और वे जितना प्रिंट कर सकते हैं उससे अधिक प्रिंट कर रहे हैं ? और इसका उत्तर यह है कि हां, आज भी अमरीका के पास वह विश्वास है। इसलिए उसके पास चालू खाता सरप्लस नहीं होगा, लेकिन विश्व के बाज़ार में यह विश्वास नहीं होगा कि अमरीका अपने कर्ज़ पर उच्च इन्फ्लेशन के माध्यम से व्यवहार करेगा। इसीलिए वह रिज़र्व करेंसी है। लेकिन यदि अमरीका की राजकोषीय स्थिति तितर-बितर हो जाती है या यह आभास हो कि उनकी पात्रता नियंत्रण में नहीं है तो अमरीका के लिए सबसे बड़ी समस्या, दीर्घकाल में यह होगी कि उनका दायित्व स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रति ज्यादा है न कि लोक ऋण के प्रति। उन्हें पेंशन आदि को नियंत्रण में लाना होगा। अमरीका में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी चिंता इस संबंध में है। लेकिन जब तक विश्व को यह विश्वास है कि एक न एक दिन वह उसे नियंत्रण में लाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है कि अमरीका कर्ज चुकाने में कोई चूक करेगा। जहां तक अन्य देशों का संबंध है, समय के साथ जब बाज़ार में चलनिधि और बढ़ जाएगी और जैसाकि कभी कम कभी ज्यादा की स्थिति चल रही है करेंसी आसानी से उपलब्ध रहेगी, इसलिए वह काफी हद तक रिज़र्व करेंसी बन जाएगी। हम इसके लिए कुछ कदम निश्चित ही उठा रहे हैं, अरविंद की बातों को ध्यान में रखते हुए, हमें उतना सब कुछ नहीं चाहिए जितनी पूंजी आज आ रही है, बल्कि रुपया बाण्ड, जीने मसाला बाण्ड कहा जाता है, अब हम विदेश में जारी कर रहे हैं, हमारे इक्विटी बाज़ार विदेशी निवेशकों के लिए खुले हुए हैं, हम उनके ऋण- बाज़ार में आने से थोड़े सावधान ज़रूर हैं, इसलिए समय बीतने के साथ-साथ जैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमारी स्वयं की घरेलू बाज़ार गहन होती जाएगी, हम भी निश्चित रूप से रिज़र्व करेंसी बन जाएंगे।

अरविंद सुब्रमणियन : आपका प्रश्न निश्चित रूप से बहुत अच्छा था।

एनडीटीवी : शायद इसलिए कि वे सेंट स्टीफन से हैं ?

अरविंद सुब्रमणियन : नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहां अनेक प्रकार के रोचक बातें उठाई गई हैं। मैंने चीन के बारे में थोड़ा कार्य किया है, और मेरी भविष्यवाणी है कि वर्ष 2030 तक चीन की करेंसी डालर से आगे निकल जाएगी और प्राइमरी रिज़र्व करेंसी बन जाएगी। यह भी हो सकता है कि मेरा कहना सही न हो।

एनडीटीवी : इसलिए दीर्घकाल के बारे में भविष्यवाणी करना सुरक्षित नहीं है ?

अरविंद सुब्रमणियन : लेकिन मेरे विचार से यहां दिलचस्प प्रश्न यह है कि जैसा कि आप जानते है . . . .

एनडीटीवी : लेकिन है तो रोचक प्रश्न

अरविंद सुब्रमणियन : जी, सच तो यह है कि चीन हमेशा से डालर को रिज़र्व करेंसी के रूप में बने रहने का विरोध करता रहा है, और वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उनकी करेंसी वह रूतबा प्राप्त कर ले। लेकिन विडंबना यह है कि जो देश पिछले 7-10 वर्षों से डालर को रिज़र्व करेंसी के रूप में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है वह है चीन। वे डालर खरीदते रहे हैं और सबसे अधिक खरीद रहे हैं। लेकिन आज विश्व में दूसरी विडंबना यह है कि डालर में रिज़र्व हासिल करके चीन के पास इतना डालर हो गया है कि वह अमरीकी फेडरल से ज्यादा डालर दे सकता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि राजनीतिक कारणों से वह अपनी पसंद के हिसाब से डालर प्रिंट नहीं कर सकता है। लेकिन

चीन चार ट्रिलियन डालर का उपयोग भू-राजनैतिक लाभ उठाने के लिए करता रहा है। इस संबंध में और भी अनेक विडंबनाएं हैं। और उम्मीद है कि किसी समय हम भी रिज़र्व करेंसी बन जाएं लेकिन तब तक, . . . देखा जाएगा।

एनडीटीवी : क्या आप 2030 तक तो नहीं कहना चाहते हैं।

अरविंद सुब्रमणियन : नहीं, मैं 2030 नहीं कहना चाहता। मैं नहीं चाहता कि 2030 तक रिज़र्व करेंसी बने। क्योंकि फिर उसका मतलब यह होगा कि हमने स्वयं को खुला छोड़ दिया है, जो उदाहरण के लिए मेक इन इंडिया के लिए सदैव वांछित नहीं होगा।

एनडीटीवी : विनिमय दर के बारे में एक बात और कहना है, जिसे पुराने समय में कोई नहीं कहता था, वह यह है कि आप रुपए को नीचे नहीं गिरने देंगे, मुझे इस गिरने, मूल्य घटने जैसे शब्द से नफरत है, आप जानते ही हैं कि यह अधिक स्पर्धी बन जाता है।

रघुराम राजन : अचानक गिरना

एनडीटीवी : अथवा ये अचानक गिरावट तेल के कारण हो, हम इतना तेल आयात करते हैं कि यदि नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। अब तेल की कीमतें काफी गिर चुकी हैं और विभिन्न संस्थाओं ने यह आलोचना की है कि आप तेल की कीमत में भारी गिरावट से होने वाले फायदे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। पहले 120 डालर था, अब 50 डालर हो गया है, और हम तेल आयात करने वाले देश हैं, यही सही समय है कि हम अपने उद्योग को खूब बढ़ावा दें, अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ने दें, हमें इसमें से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई प्रभाव नज़र नहीं आता है? सबसे बढ़कर तो इस समय उद्योग जगत समस्याओं से जूझ रहा है। मैं जानता हूँ कि आप उपभोक्ता की ओर देखेंगे लेकिन उद्योगपति भी एक संकेत की तरह हैं, वे अर्थव्यवस्था की बहाली के प्रारंभिक संकेत हैं। आइए हम देखते हैं कि आज हमारा उद्योग कौन-कौन सी समस्याओं का सामना कर रहा है। यह वास्तव में गंभीर बात है, यह बात सुर्खियों में लिखी गई है कि उनके भीतर संकट के आसार नज़र आते हैं। हाल की तिमाही में तीन में से दो कंपनियां अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकीं, हैरत की बात है बिलकुल अप्रत्याशित सा है। उद्योग की वृद्धि दर 5 प्रतिशत है, मैं बात कर रहा हूँ चीन की, उन दिनों 18 प्रतिशत, 19 प्रतिशत औद्योगिक वृद्धि दर हुआ करती थी। नये रोजगार की हालत खस्ता है, संगठित क्षेत्र में 2015 की एक तिमाही में केवल 64,000 रोजगार पैदा हुए हैं। यह अचंभित करने वाली सबसे न्यूनतम स्थिति है, क्या इसका कोई हल नहीं है। निर्यात गिर रहा है अभी हमने चर्चा की, हो सकता है 24 प्रतिशत या उससे थोड़ा अधिक हो, जो कि मुद्रास्फीति के अंतर पर निर्भर करेगा। प्रतिस्पर्धा, हम 186 में से 130वें पायदान पर हैं, 10 पायदान ऊपर उठे हैं। क्या बात है साहब, हम 142 से उठकर इस स्थिति में आ गए हैं। आप जानते हैं कि फुटबाल में हमारी स्थिति कहां पर है? मेरे विचार से हम शायद 120वें स्थान पर हैं, हम फुटबाल खेलने वाले राष्ट्रों में 120वें स्थान पर अच्छे हैं। प्रतिस्पर्धा वाले देशों में हमारा स्थान 130वां है, 56 ऐसे देश हमसे नीचे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। और उस पर ऊंचे कर्ज का बोझ है जिसे सभी उद्योग को चुकाने की आवश्यकता है, इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इस तरह देखें तो आज उद्योग रो रहा है, और हमने उसके लिए अभी तक कितना कुछ किया है? इन स्थितियों पर तेज़ी से एक नज़र डालें, और आप एक काम कर सकते हैं, वह है ब्याज दर में बदलाव। अन्य चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है मात्रात्मक सहजता, अधिक सरकारी व्यय, लेकिन डाटा से पता चलता है कि सरकारी खर्च कम हो रहा है, एक नज़र जीडीपी के प्रतिशत पर डालें, सरकारी व्यय जो एक तरह से संवृद्धि को धीमा करता है, हो सकता है यह ग्राफ और अधिक व्यय की स्थिति दिखा सकता था, इन्हें ग्राफ बनाना सीखने की ज़रूरत है, क्या यह नहीं दिखाई दे रहा है कि वह 17 प्रतिशत से घटकर जीडीपी के 13.5 प्रतिशत तक गिर गया है। हमने यही किया है कि इस वर्ष विनिवेश का कोई लक्ष्य नहीं रखा है ? मेरे विचार से केवल एक क्षेत्र ऐसा है जो उचित रूप से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, वह है निर्माण क्षेत्र। सरकार खर्च कर रही है ताकि अर्थव्यवस्था में तेजी आए, जो आपका क्षेत्र है, केवल आपके क्षेत्र की बात नहीं है, कई मंत्रालय है जो अर्थव्यवस्था को तेजी नहीं प्रदान कर रहे हैं, इसलिए केवल ब्याजदर की क्या बात करें।

अरविंद सुब्रमणियन : आपने मेरे विचार से दो प्रश्न किए हैं, एक तो विनिर्माण (मैनुफैक्चरिंग) के बारे में और दूसरा प्रश्न सरकार के बारे में ?

एनडीटीवी : जीहां, जीहां

अरविंद सुब्रमणियन : मैं नहीं जानता कि इस बात को आप किस प्रकार लेंगे, यहां मैं निजी मैनुफैक्चरिंग के बारे में बात करूंगा। मेरे विचार से इन समस्याओं की भलीभांति शिनाख्त की गई है, किंतु इसे मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। मैं समझता हूं कि आज भारतीय अर्थव्यवथा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यहां निवेश कमज़ोर क्यों है ? और इसके अनेक कारण हैं। इसका एक कारण यह है कि निजी क्षेत्र के तुलनपत्र दबाव में हैं।

एनडीटीवी : आपका मतलब है कि उनपर कर्ज बहुत ज्यादा है ?

अरविंद सुब्रमणियन : जी, काफी कर्ज है। इसका यह भी अर्थ होता है कि जब कर्ज ज्यादा हो जाता है तब लाभ कम हो जाता है, है कि नहीं? ऐसा लगता है कि ये कुछ क्षेत्र में कुछ समूह में जम गया है। मेरे विचार से इसपर ध्यान देना जरूरी है, चूंकि कर्ज ज्यादा है, वे कमज़ोर

हो चुके हैं, इसीलिए निवेश नहीं कर सकते। इस समस्या का एक अंश यह भी है कि गुजरे हुए 2000 के दशक से यह चीज विरासत में मिली है, जब बहुत अधिक संवृद्धि की उम्मीद की गई थी और उन्होंने स्वयं को अत्यधिक लीवरेज्ड कर लिया था। कुछ हद तक उस स्थिति ने अड्डा सा जमा लिया है। मैं समझता हूँ कि चुनौती इस बात की है कि फर्मों के तुलनपत्र को साफ-सुथरा कैसे बनाया जाए। हम बैंकों के तुलनपत्रों को भी साफ-सुथरा कैसे बनाएं। मेरे हिसाब से जब तक हम इन दोनों समस्याओं को नहीं सुलझाते है तब तक आगे भी निजी निवेश कमज़ोर ही बना रहेगा। हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन तब यही बात सामने आती है कि निजी निवेश कमज़ोर होता जा रहा है तो उसे सरकार कितना समायोजित करेगी ?

एनडीटीवी : आपको क्या करना है ? जागना है और कुछ करना है।

रघुराम राजन : मैं समझता हूँ कि सरकार जागरूक है . . .

एनडीटीवी : मेरी समझ से वे आपसे ब्याज दरें कम करने के लिए कह रहे हैं ताकि उद्योग में तेजी आए, इसके लिए आप क्या करेंगे ?

रघुराम राजन : मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर खर्चे सरकार उठाने जा रही है, निश्चित रूप से सड़क क्षेत्र में तेजी आई है, रेलवे के बारे में उम्मीद है कि बहुत जल्दी उसमें भी तेजी आएगी, यही वे कार्य हैं जिन्हें किया जाना आवश्यक है। देखना यह है कि इसमें किस रफतार से प्रगति होती है, लेकिन प्रयास जारी है। अरविंद ने जो बातें कही हैं वे महत्वपूर्ण हैं, कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा लीवरेज लिया है, और निवेश करना बंद कर दिया है। कर्ज बहुत अधिक है, चूंकि कर्ज बहुत ज्यादा है इसलिए नये सिरे से धन ले भी नहीं सकते और न ही निवेश कर सकते हैं। यह एक बात हुई। लेकिन हमें यह भी याद रहना चाहिए कि दो मानसून के मौसम खराब रहे हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से भी मांग कमज़ोर बनी रही है। इस तरह विदेश से मांग कमज़ोर है जैसाकि आपने पहले ही कहा है, ग्रामीण मांग कमज़ोर है, निवेश कमज़ोर है, कम से कम निजी निवेश को उभरने में अभी समय लगेगा। इस प्रकार, कुल मिलाकर कंपनियां, यहां तक कि रेगुलर कंपनियां, न केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर, न कि ऐसी सामग्रियों वाली जिन्होंने गुज़रे वर्षों में मांग के चलते लाभ उठाया है, जब वे कहती हैं कि पर्याप्त नहीं है, जो उक्त कारणों का हिस्सा है, इसलिए वस्तुतः हम ब्याज दरों में उतनी कटौती करते हैं जितना कि हाल में हमने की है, जब लोग दर में कमी किए जाने की अपेक्षा करने लगते हैं। लेकिन इन बातों के होते हुए कुछ संकेत ऐसे हैं जो यह बताते हैं कि कुछ चीजों में तेजी पैदा होना शुरू हो गई है, आटो सेक्टर को देखें, वर्ष-दर-वर्ष 22 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, इस बात के कहीं न कहीं संकेत अवश्य हैं, कम से कम शहरी मांग ज़्यादा विश्वसनीय रूप से बढ़ रही है, शायद इसलिए कि आय अधिक है और खर्च कम है, क्योंकि ईंधन आदि सस्ता हुआ है।

एनडीटीवी : क्या यह कुछ ज़्यादा ही आशावादी नहीं है ? अधिकांश उद्योगपति यह कहते हुए सुने गए हैं कि आप इस समय चाहे जो कर लो कुछ भी सही नहीं उतरता है।

रघुराम राजन : आप बताते जाएं यह रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। मैं स्वयं भी वित्त मंत्रालय में रह चुका हूँ।

एनडीटीवी : उन्होंने कब यह कहा है कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है ?

रघुराम राजन : इतना भी नहीं है। मैं समझता हूँ उन्होंने हमेशा अच्छी भावनाएं व्यक्त की हैं।

एनडीटीवी : यह सही है कि वे आपके प्रति सम्मान दिखाते हैं, लेकिन जब आप कक्ष में उपस्थित नहीं होते तब वे कुछ और ही कहते हैं ?

रघुराम राजन : ऐसा नहीं है, वे हमेशा अपनी परिस्थितियों के अनुसार होने वाली कठिनाइयों के बारे में बात करते हैं और हम दोनों उनके इस विचार से सहानुभूति रखते हैं कि यह वास्तव में बड़ी कठिन परिस्थिति है और ऐसा भी समय आने वाला है कि वे एकजुट होकर अचानक आपको चोट पहुंचाएंगे, आप जानते ही है कि अचानक सब कुछ ठप्प करके, इसलिए ये बहुत कठिन घड़ी है। मैं समझता हूँ कि सरकार, रिज़र्व बैंक और हम सब इससे सहमत हैं लेकिन हमें उन्हीं उपकरणों के साथ कार्य करना पड़ता जो हमारे पास उपलब्ध हैं।

एनडीटीवी : क्या वित्त मंत्रालय या सरकार इससे ज़्यादा नहीं कर सकती है ?

अरविंद सुब्रमणियन : मेरे विचार से . . . . .

एनडीटीवी : सर, शायद आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं।

अरविंद सुब्रमणियन : नहीं, मैं कहना चाहता हूँ . . . .

रघुराम राजन : दरअसल सवाल यह है कि मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन की गति क्या है, मेरे विचार से हम दोनों यथासंभव कोशिश कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैक्रो-स्थिरता बनाए रखने की कितनी आवश्यकता है। इसलिए इसमें जो चीज शेष रह जाती है वह है वित्तीय क्षेत्र में संरचनागत सुधार की गति को मज़बूती प्रदान करना, जिसपर हम ध्यान दे रहे हैं। नये बैंक प्रारंभ हो रहे हैं, उदाहरण के लिए बंधन बैंक काफी लोगों को ले रहा है, आईडीएफसी काफी लोगों को ले रहा है, वे वो सब कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए।

और इसी प्रकार ये सब नये भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक वे भी लोगों को लेंगे और जो आर्थिक प्रगति में सहायक बनेंगे।

एनडीटीवी : उन्हें क्या करना चाहिए ?

रघुराम राजन : जैसाकि मैंने अभी कहा कि वे लोक निवेश करने का प्रयास करेंगे जो गति पकड़ रहा है . .

एनडीटीवी : शायद ये गति नहीं पकड़ रहा है ?

अरविंद सुब्रमणियन : नहीं ऐसी बात नहीं है, ये याद रखें कि लोक-निवेश में केवल सड़क ही नहीं है बल्कि रेलवे में भी तेजी आ रही है और दोनों योगदान दे रहे हैं, पिछले छह महीने में वास्तव में वृद्धि 18 प्रतिशत थी, सड़क रेलवे सभी में और हमने वर्ष के बजट का लगभग 53 प्रतिशत व्यय कर दिया है और यह उल्लेखनीय है कि लोक-निवेश निजी क्षेत्र के लिए अच्छा है क्योंकि इससे क्षमता का सृजन हो रहा है, इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है जिसमें निजी निवेश की भीड़ जुटेगी। लेकिन, प्रणय में इससे भी बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि उस बात में सुधार है जो आप नहीं कह रहे हैं, शायद आप जो बात कहने का प्रयास कर रहे हैं वह थोड़ी अस्पष्ट सी है।

एनडीटीवी : मैं अपने आइडिया से, और ईमानदारी से कहूँ तो कई वर्षों से उद्योगपतियों से जो सुनते आया हूँ, वही कह रहा हूँ। मैंने उन्हें कभी कहते हुए नहीं सुना है और ये बात वे कभी आपसे नहीं वास्तव में नहीं कहते हैं, क्योंकि वे डरते हैं, ये ऐसी स्थिति है, लाचार जैसी . . . .

अरविंद सुब्रमणियन : मेरी समझ से हमें यहां पूरे परिदृश्य को समझना होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसके बारे में सही तरीके से सोचा जाए बजाय यह सोचने के कि विश्व में क्या हो रहा है, आप जानते ही है कि मांग गिरती जा रही है, निजी निवेश की ऐसी हालत के बावजूद हम तेजी से प्रगति कर रहे हैं। जरा सोचिए पिछले वर्षों में जब हम 10, 9.5 प्रतिशत की दर से विकास कर रहे थे तब हमारा निर्यात 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा था, लेकिन अब निर्यात वृद्धि शून्य प्रतिशत होती जा रही के बावजूद हम 7, 7.5, 8 प्रतिशत जो भी हो, कर रहे हैं, ये 7.5, 8 प्रतिशत की दर से हो सकती है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं. .

एनडीटीवी : हम पूरी श्रृंखला की बात कर रहे हैं ? ठीक है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे।

अरविंद सुब्रमणियन : हम इसपर बाद में आएंगे। लेकिन इसे हमें विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, विश्व में मंदी आती जा रही है, प्रत्येक देश में मंदी की स्थिति है और इसके होते हुए भी हमारे देश में मैक्रो-स्थिरता का बेहतरीन दौर बना हुआ है और वास्तव में निवेश के बेहतरीन अवसर उपलब्ध हैं, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था को इस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं . . .

एनडीटीवी : क्योंकि ये सब बातें बिलकुल सही हैं, हमारी मैक्रो-स्थिरता बेहतरीन है। आप दोनों को इसके लिए धन्यवाद, मेरे विचार से सरकार ने अब तक सबसे अच्छा काम आप दोनों को नियुक्त करके किया है जिसमें मैं नहीं हूँ, मैं यह कहना चाहता हूँ यदि आप अपने स्थान पर न हों तो। लेकिन मुद्दा यह है, जिसके बारे में वे बाते करते रहे हैं, और इसे वे खुलकर एक या दो ने तो कैमरे के सामने कहा है, हालांकि वे थोड़े हिचक रहे थे। लोग निवेश करते समय भारत में जिस चीज को पसंद करते हैं वह है स्थिरता और लोकतंत्र, सहिष्णुता, विभिन्न धर्मों, जातियों की स्वीकार्यता, आप जानते ही हैं कि यहां सभी लोग मिल-जुलकर रहते हैं। हमारे देश की स्थिति विश्व के अन्य देशों से भिन्न है। अब वे चिंतित हैं, मैंने विदेशी निवेशकों को कहते सुना है, कि भारत में क्या हो रहा है, अर्थात उसे सहिष्णुता में बदलाव आ गया है जिसके लिए भारत को जाना जाता था, क्या यह स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी ?

रघुराम राजन : मेरे विचार से लोगों की भावनाओं को किसी विशेष क्रियाओं और हरकतों के माध्यम से भडकाया गया है जो पूरी सच्चाई को प्रदर्शित नहीं करती है। इसलिए समझदारी इस बात में है कि हमें सावधानी बरतनी होगी कि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी बातें तेजी से फैलती हैं जिसे पूरा विश्व जान जाता है।

अरविंद सुब्रमणियन : इस समय की स्थिति भी इसमें शामिल है।

रघुराम राजन : इस समय की भी मेरे विचार से यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वित्त मंत्री ने कई बार यह बात कही है कि इसके बारे में हमें सावधानी बरतनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही जायज़ सलाह है।

एनडीटीवी : लेकिन ये तो जारी है, मेरे कहने का मतलब कि भारत किस बात के लिए जाना जाता था। अब अचानक एक ऐसा देश बन गया है जहां सहिष्णुता का अभाव है, यह एक भयावह परिवर्तन है, है कि नहीं ? और ऐसा क्या है कि यह रूकने का नाम नहीं ले रहा है।

रघुराम राजन : मैं दुबारा यह बात कहूँगा कि जो मुद्दा है उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। और सरकार के वरिष्ठ सदस्य से जिनकी ओर से मैं बोलने जा रहा हूँ, जिसे वह ऐसा नहीं चाहेंगे, शांत हैं और निश्चित रूपसे उनकी सलाह उपयुक्त सलाह है। हमें पूरे परिदृश्य में शांत हो जाना चाहिए क्योंकि जैसाकि आपने कहा ये हमारे इतिहास, हमारी विरासत, हमारी सहिष्णुता तथा हमारे खुलेपन को उजागर करता है।

एनडीटीवी : मेरे कहने का तात्पर्य भी यही है कि ये भारत का बहुत बड़ा सकारात्मक पक्ष है, और यदि इसे हम छोड़ देते हैं तो स्थिति खतरनाक होगी।

रघुराम राजन : मेरे विचार से स्थिति सकारात्मक बनी रहेगी क्योंकि यह हमारा आंतरिक इनाम है, सभ्यता का इनाम है, स्वतंत्रता का इनाम है और हमें सावधान रहना होगा कि अतिशयता कहीं इन चीजों को अगुवा न कर ले जाए जो काफी संतुलित और हमारे केंद्र में मौजूद है।

एनडीटीवी : अब आप इस प्रकार जवाब दे सकते हैं जैसे कि आप इस कक्ष में नहीं बैठे हैं।

अरविंद सुब्रमणियन : ठीक है, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, एक तो उसके बारे में जो मैंने और रघु ने संयुक्त रूप से पूरे विश्व के लिए किया है, मेरे विचार से नियम के प्रति निष्ठा यह है कि देश किस प्रकार से सामाजिक भेदभाव को सामाजिक असंतोष को नियंत्रित करता है, यही दीर्घकालिक विकास के प्रमुख निर्धारक हैं, यही नियम के प्रति निष्ठा है।

एनडीटीवी : तो ये दीर्घकालिक विकास के प्रमुख निर्धारक हैं।

अरविंद सुब्रमणियन : मैं समझता हूँ कि यह बात सरकार में और बाहर सभी अच्छी तरह जानते हैं, सभी समझते हैं कि यह अनिवार्य जरूरत है। जैसाकि रघुने कहा कि वित्त मंत्री जी निरंतर यह कह रहे हैं कि हमारी कार्यसूची विकास की है, हमें उसपर ध्यान देना है, उससे ध्यान नहीं हटना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह जैसाकि आप दोनों ने कहा कि हमारे पास है, निःसंदेह है किंतु हमें यथासंभव उन्हें सावधानीपूर्वक पोषित करना होगा। लेकिन हमें अपनी समुत्थान-शक्ति में भी विश्वास रखना होगा कि ये हमारी शक्ति है, इसे हम बनाए रखेंगे, उसके लिए कार्य करते रहेंगे और निरंतर कायम रखेंगे और यही चीज मध्यावधि के लिए अच्छे शकुन का कार्य करेगी।

एनडीटीवी : लेकिन जो घट रहा है आप उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, क्या नहीं. ?

अरविंद सुब्रमणियन : रघु, मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी चीज जिसकी अतिशयता हो या सहन योग्य न हो, कोई उसे पसंद नहीं करेगा, चाहे लोग हों, सरकार हो या सभी सरकारें।

एनडीटीवी : असहिष्णुता के बारे में कोई प्रश्न ?

श्रोता 3 : मेरा प्रश्न डॉ. सुब्रमणियन से है। सर, हालही में हमने मूडी की रिपोर्ट देखा है जिसमें भी इस मुद्दे का उल्लेख किया गया है और यदि आप इस मामले के गुण-दोष पर ध्यान दिए बिना पूरी तरह से उसके व्यावहारिक पक्ष को देखें तो आपको क्या लगता है कि जो हो रहा है वह सही है या गलत, आपके लिए शायद यह बहुत मुश्किल होगा कि भूमि अधिग्रहण, जीएसटी जैसे सुधार को राज्य सभा में बहस के लिए रखे बिना आगे बढ़ा लें और यह चीज विरोधी पार्टी को सभा को बाधित करने के लिए पर्याप्त खुराक मुहैया करा देती है। इसलिए सरकार की इस स्थिति से निपटने की क्या रणनीति है क्योंकि यह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय यह देखने के कि जो घटित हो गया वह कितना सही या गलत था ? उनकी जांच तो चलती रहेगी। पूरी अर्थव्यवस्था के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सरकार की योजना क्या है जिससे वह राज्य सभा के साथ प्राथमिक रूप से बातचीत करेगी।

एनडीटीवी : यह बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है। मैं मूडी के बारे में एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। मूडी रिपोर्ट के दो भाग हैं। मूडी विश्लेषण और मूडी निवेश सुधार। एक रेटिंग के बारे में होती है जिसकी उतनी आलोचना नहीं की गई है, मूडी के विश्लेषण वाले भाग में ऐसा है, लेकिन यह निश्चित है कि मूडी निवेश खंड मूडी विश्लेषण की बात दीर्घकाल में जरूर सुनता है या फिर यह भी हो सकता है कि परवाह ही न करे।

अरविंद सुब्रमणियन : लेकिन पहली बात यह है कि मूडी ने जो कहा है वह अनुभवजन्य अनुसंस्थान पर आधारित नियम-निष्ठा के बारे में हैं, जो वे केवल सावधान करने हेतु लिख रहे हैं। आपका प्रश्न राजनैतिक रणनीति के बारे में है और मैं किसी के लिए भी राजनैतिक रणनीति नहीं बनाता, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है . . . .

एनडीटीवी : यदि आपका मानना है कि राजनैतिक रणनीति ठीक थी तो क्या आप यह कह सकते हैं कि ये सब कुछ जो हुआ सब ठीक था ?

श्रोता 3 : नहीं सर, अंततः इसमें समस्या दूसरी ओर से भी उठ सकती है, फिर उद्योग हमारे देश में नहीं आना चाहेंगे।

अरविंद सुब्रमणियन : लेकिन इसके मुख्य मुद्दे को अच्छी तरह समझ लिया गया है और इस मुद्दे को वित्त मंत्री भी कह चुके हैं कि इसके लिए हमें विधायी कार्यसूची पारित करने हेतु सभी का समर्थन चाहिए ताकि यदि कुछ किया जाना हो तो उसे करने का प्रयास किया जाए और कर लिया जाए।

एनडीटीवी : यह बात वित्त मंत्री कह रहे हैं, लेकिन इस बात को क्या पूरी शिद्दत के साथ मुखर होकर कहा गया है ? मुझे पता है कि बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह सही नहीं है, लेकिन लोगों के बीच आप हमें अच्छी तरह नहीं सुनते हैं। क्या आपका मानना है कि यह बात और जोर से कही जानी चाहिए?

रघुराम राजन : देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां प्रेस चौबीस घंटे काम कर रहा है और प्रेस कुछ बातों को उठा लेता है और कुछ बातों को नहीं उठाता है। मैं समझता हूँ कि हाल में सरकार की ओर से अनेक बार आवाज़ उठाई गई है, जिसे अब जोड़ा जा रहा है, किंतु पर्यावरण मंत्री ने इसके बारे में पूर्व में ही बताया था कि ये बातें हो चुकी हैं किंतु उसे नहीं उठाया गया।

एनडीटीवी : आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं?

रघुराम राजन : नहीं, मैं मीडिया पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि यह स्पष्ट नहीं है कि जब आप यह कहते हो कि उन्होंने पर्याप्त रूप से नहीं कहा है।

एनडीटीवी : क्या संकेत बाहर जा चुके हैं? जैसे कि हम विभिन्न प्रकार के उद्योगों के संकेत के बारे में बात कर रहे हैं, उनके इस असहिष्णुता को रोक देने का संकेत और वापस देश की अद्भुत विशेषता की ओर जाने का संकेत।

रघुराम राजन : यह हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि ऐसा कहना जारी रखें, हम इसे पर्याप्त नहीं मानते तो यदि इसे कहते रहें और हर मोर्चे पर शिद्दत से कहते रहें तो मैं समझता हूँ कि हम वो चीज अक्षुण्ण बनाए रख सकेंगे जो इस देश में बनाए रखना ज़रूरी है। और यह बात मैंने कही, दूसरे भी कह रहे हैं, हम बस कहते जाएं तो हमारी आवाज़ से दूसरी आवजें जुड़ती जाएंगी।

एनडीटीवी : हम अपनी वृद्धि दर के बारे में बात करें, 7 से 8 प्रतिशत के बीच रहती है, क्या यह अतुल्य है, या कि कोई समस्या है, पूरा विश्व आपकी ओर देख रहा है, क्या वाकई आप 7-8 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहे हैं ? संपूर्ण विश्व 2-5 प्रतिशत की दर से विकास कर रहा है, चीन की विकास दर नीचे आ रही है और सच तो यह है कि जब मैं अपने कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों की ओर देखता हूँ तो मुझे 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि नहीं दिखाई देती है। एक नज़र डालिए नये जीडीपी की विश्वसनीयता के पीछे कुछ तथ्यों पर। पहली बात तो यह है कि हमारे उद्योग में वृद्धि काफी धीमी है, 5 प्रतिशत से कम है। आपने दो खराब मानसून की बात की है, निर्यात घट रहा है, विश्व की वृद्धि कमज़ोर होती जा रही है और क्या हमारी स्थिति संकट के बाद बिल्कुल पटरी से बाहर हो गई है ? हमने खराब मानसून के बारे में बात की है, तो किस तरह से हम इस मंदी के माहौल में कह सकते हैं कि हमारी वृद्धि दर 7 से 8 प्रतिशत के बीच है और उसमें परिवर्तन भी हो सकता है ? मैं आपको वास्तविक हेडलाइन बता सकता हूँ जिसमें थोड़ी सारणी भी है। हम उस परिवर्तन को देखें जिसने मूलतः पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है और उसके चलते विश्वसनीयता भी थोड़ी सी डगमगा गई है, हमारा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन एक महान संस्था है, लेकिन जब हम पूर्व की श्रृंखला को देखते हैं तो 2013-14 में वृद्धि दर 5 प्रतिशत थी जिसे उन्होंने बाद में संशोधित किया था और आपने इसे संशोधित करके 6.9 प्रतिशत कर दिया था? मेरे कहने का आशय यह है कि आप संशोधन 5 से 5.2 प्रतिशत या 4.8 प्रतिशत या 5.3 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशत तक कर सकते हैं, जो 40 प्रतिशत परिवर्तन करने जैसा है, ऐसा लगता है कि हमारी सांख्यिकीय पद्धति गज़ब की है जिसमें कोई साफ-साफ स्पष्टीकरण नहीं है। इस तरह 6.9 से 7.8 प्रतिशत की वृद्धि से बाज़ार को मिलने वाले लाभ से इतर देखें तो डाटा के संबंध में विश्वसनीयता की समस्या दिखाई देती है। हम इस विश्वसनीयता की समस्या को कब समाप्त करेंगे ? क्योंकि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हर कोई इन आंकड़ों के बारे में बातें करता है, चीन ने इस समस्या को समाप्त कर लिया है, लेकिन भारत ने ?

रघुराम राजन : हम वही आंकड़े लेते हैं जो हमें सरकार से प्राप्त होते हैं . . . .

एनडीटीवी : और आपको उन आंकड़ों पर विश्वास नहीं होता है ?

अरविंद सुब्रमणियन : मेरे मित्र ने जो बात अभी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत की है, मेरे विचार से चीन के साथ तुलना, जीडीपी मापने के लिए हमारे पास जो व्यवस्था और संस्था है, संपूर्ण सांख्यिकीय व्यवस्था, वह त्रुटिहीन है और उसकी निष्ठा गैर-चुनौतीपूर्ण है। प्रक्रिया अति उत्तम है और वस्तुतः विडंबना यह है कि ये जितने भी संशोधन किए गए हैं हमारे मानक को विश्व स्तरीय बनाने के लिए किए गए हैं, और जो ये धुंआधार नई जानकारियां उपलब्ध हो रही हैं उनका उपयोग करने के लिए और यही वजह है कि इतने सारे संशोधन हुए हैं। मैं यह भी कहूंगा कि कभी-कभी तो इनकी प्रक्रियाएं बहुत अच्छी होती है लेकिन परिणाम के बारे में आप हमेशा निश्चित नहीं हो सकते हैं। मेरा सबसे बढ़िया उदाहरण अमरीका है, वे श्री बुश को पुनः निर्वाचित करने में सफल रहे, लेकिन जब हम उसकी महत्ता का मूल्यांकन करते हैं, तो पाते हैं कि यह संशोधन का पहला स्तर है, इस बात का पता लगाने के लिए कि यह समझदारी थी या नहीं, वे डाटा के बारे में कार्य करने जा रहे हैं, मेरे विचार से उन्हें ऐतिहासिक श्रृंखला निकालना चहिए ताकि . . . . के विपरीत प्रामाणिक सिद्ध कर सकें।

एनडीटीवी : ये तो ऐसी बात हुई कि कितने साल बीत गए हैं इसलिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एक महान संगठन बन गया है, वैसे भी हमेशा महान संगठन रहा है, इसलिए 5 प्रतिशत ठीक-ठीक था, इतना खराब नहीं था, लेकिन अब वह सब गलत हो गया है।

रघुराम राजन : प्रणय, जैसाकि अरविंद ने कहा है कि समय बीतने के साथ-साथ हमें पता चलेगा कि हमें किस चीज की कमी है या फिर हमारा अनुमान जरूरत से ज़्यादा है। मेरा मतलब है कि यह स्थिति सबसे अच्छी है और हमें इसपर अभीसे काम करना शुरू कर देना

चाहिए। यह कहा गया है कि हम 2 पर है या 1 पर ? नहीं, मेरे विचार से अधिकांश विश्लेषक यह कहेंगे कि इस समय 1 प्रतिशत वृद्धि में इस तरह की अनियमितता है, उस तरह की अनियमितता है, और कुछ का कहना उस प्रकार होगा जो हम 7 प्रतिशत जैसा सोच रहे हैं, पुराने नंबरों को देखते हुए और उद्योग 7 प्रतिशत के बारे में क्या सोच रही है कि कैसा लग रहा है। और इसलिए पुराने नंबर हो सकता है गलत या सही रहे हों ? और हम शायद थोड़ा बेहतर जा रहे हों, लेकिन ये सब हम एकतरफ रखेंगे . . .

एनडीटीवी : लेकिन आप जानते ही हैं कि उन सबको अलग कर दिया गया है, उद्योग की वृद्धि धीमी है, लगातार दो मानसून खराब था, निर्यात कम था और उसपर वृद्धि दर 7 से 8 प्रतिशत, ये कुछ हल नहीं हो रहा।

रघुराम राजन : सच्चाई नये एवं पुराने नंबरों के समीकरण में हैं। मैं समझता हूँ कि श्री प्रणय सेन ने जो बात कही है वह एक के प्रति एक नहीं है। हम संभवतः, यदि यह कहें कि पुराने वृद्धि के नंबरों के अनुसार इसका क्या अर्थ है, तो हम उस स्थिति से थोड़ा नीचे चले जाएंगे जहां हम इस समय हैं, इसलिए मेरा मानना है कि अधिकांश सांख्यिकीविद यह कहेंगे कि फिर कौन सा सही है ? जैसाकि अरविंद ने कहा है कि नये नंबरों में बेहतर तकनीक शामिल है, लेकिन जीडीपी के आकलन में सदैव बड़ी उदात्त मान्यताएं दी जाती हैं और आप जैसे विद्यार्थी जब उसकी तह में जाते हैं तो यह भी ऐसी चीज है जिसे समझदार अर्थशास्त्री को करना चाहिए और उसके भीतर जाकर यह पता लगाना चाहिए कि इसका सही-सही आकलन किस प्रकार किया गया है। और आप देखेंगे कि कई स्थानों पर तो कोई डाटा ही नहीं होता है और आपको मान्य करना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है, और इस तरह उसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहती है और समय बीतने के साथ-साथ हम उसमें सुधार करेंगे।

अरविंद सुब्रमणियन : मुझे इसमें एक-दो बातें जोड़नी हैं . .

एनडीटीवी : जो कोई सवाल पूछना चाहते हैं वे अपना हाथ उठाएं। मैं इसके बाद आपके पास वापस लौटूंगा।

अरविंद सुब्रमणियन : रघु ने जो बात कही है उसी में जोड़ते हुए, मोटे तौर पर हम पुस्तक में हैं या फिर वे कम-ज्यादा वर्षों में होंगे जो वैसे तो समस्त अनुमानों के साथ आते हैं क्योंकि समस्त मान्यता जो आप मानते हैं. . . .

एनडीटीवी : आपने जो कहा उसमें मैं सुधार कर दूँ, ज्यादा-कम एक सामान्य सी स्थिति है, यहां ज़्यादा नहीं है, आप 8 प्रतिशत के ऊपर नहीं हैं। यह अभी भी ऋणात्मक ही है।

अरविंद सुब्रमणियन : ठीक है, हो सकता है यह असमान विश्वसनीयता बैंड हो जैसाकि आपने कहा, लेकिन हमें जो देखना है वह यह है कि समय बीतने के साथ चीजें कैसे बदलती हैं और क्या वर्ष 2014-15 वर्ष 2013-14 से बेहतर है ? डाटा से पता चलता है कि वर्ष 2015-16 वर्ष 2014-15 से बेहतर है, डाटा बताते हैं कि जब हम नंबरों की ओर देखते हैं तब केवल उनके स्तर को ही नहीं देखते, जो विचाराधीन होते हैं किंतु, उनमें हुए परिवर्तनों को भी देखते हैं और वही पर ये डाटा हमें सही दिशा में ले जाते हैं।

रघुराम राजन : आपका कहना बिल्कुल सही है, उद्योगपति ये कहते हैं कि स्थिति ऐसी ही है, हमारी अर्थव्यवस्था में बहाली पैदा हो रही है।

अरविंद सुब्रमणियन : अंतिम बात यह है कि मैं एक नंबर को जिसे देख रहा हूँ, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि वस्तुतः यह एक प्रकार से डालर है या रुपया है। लेकिन सरकार के लिए पहले छह महीने में अप्रत्यक्ष कर राजस्व में जो वृद्धि होती है वह वसूली गई दुर्लभ मुद्रा होती है, जो उसे तभी प्राप्त हो सकती है जब अंतर्निहित गतिविधियां अच्छी तरह से चल रही हों। और जहां तक उस नंबर की बात है, यदि आप नई चीजों को निकाल भी दें, नये कर जोड़े गए हैं, इसलिए वे नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं लगभग 11.5-12 प्रतिशत और यदि वे नंबर सही हैं तो उसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है।

एनडीटीवी : लेकिन वो तो नाममात्र ही है ?

अरविंद सुब्रमणियन : लेकिन याद रहे कि यहां हम सामान्य जीडीपी के अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति कम है। जिसका आशय बहुत कुछ होता है जो वास्तविक जीडीपी होता है।

एनडीटीवी : मुद्रास्फीति कम हो या ज्यादा, मुझे अभी भी सौ फीसदी यकीन नहीं हो रहा है। दूसरी बातें भी हैं जिनके विषय में लोग बातें करते हैं लेकिन वह पूछने से पहले मैंने आपको टोक दिया, मैं समझता हूँ कि यह कुछ खुली सी बातें हैं, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सवाल पूछने जा रहे थे और मैंने बीच में रोक दिया, अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्रोता 4 : सर, ये बातें निवेशक की भावना के बारे में थीं, आपने निवेश के प्रति खुलेपन की बात की है, आपने मेक इन इंडिया की बात है, लेकिन विश्व भर में भारत में निवेश करने के बारे में काफी निराशा है। इसलिए मैं गवर्नर से जानना चाहता हूँ कि इसको बदलने के लिए उनके क्या विचार हैं ?

रघुराम राजन : अर्थशास्त्र और वित्त में प्रमुख संकल्पना जोखिम और प्रतिफल की है और लोग भारत में कारोबार करने में किसी न किसी प्रकार की कठिनाई की शिकायत जरूर करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे यहां जरूरत से ज़्यादा नौकरशाही है। सरकार उसे कम

करना चाहती है लेकिन वह बनी हुई है। लेकिन वहीं पर यदि आप अपनी फैक्ट्री हटा लेते हैं तो आपको बहुत पैसा मिलता है, बहुत से हमारे विदेशी निवेशक हमारे यहां फैक्ट्री लगाते हैं और समय बीतने के साथ-साथ उन्हें लाभ हुआ है और वे खुश हैं, ठीक। आप देख सकते हैं कि मारूति सुजुकी, हिंदोस्तान लीवर आदि सफल हैं। इसलिए सफलता की आखिर चाबी क्या है, अभी भी कहना कठिन है, ये स्कैंडिनेविया नहीं है जिसकी सहायता से आप 7, 8, 6 जो भी हो, कुछ ऊंचा नंबर हासिल कर लें।

अरविंद सुब्रमणियन : 7 से ज़्यादा नीचे न जाएं।

रघुराम राजन : आप आज विश्व में इस प्रकार की वृद्धि कहां पाएंगे, इसलिए वे वास्तव में इन्हीं चीजों से आकर्षित होंगे और एक बार वे यह सीख गए कि कैसे करना है, कैसे यहां की जमीन पर फैक्ट्री डालना है तो फिर उनमें से ज़्यादा लोग अपने कारोबार को फैलाने में खुशी महसूस करेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि इसका उत्तर थोड़ा कठिन अवश्य है लेकिन अवसर भी बहुत अधिक हैं। थोड़ा जोखिम भी है लेकिन काफी कमाई भी है और भारत के बारे में एक ऐसी चीज है जिसे हम बेच सकते हैं, वास्तव में यहां लोगों ने तब भी पैसे बनाए हैं जब हमारी वृद्धि दर धीमी थी।

एनडीटीवी : शायद चीन से भी ज़्यादा, बहुत से लोगों का पैसा चीन में डूब गया लेकिन उन्होंने यहां पर पैसा बनाया है ।

अरविंद सुब्रमणियन : मैं दो-चार बातें कहूँगा। मेरे विचार से इस समय, चीजों को थोड़ा बराबर करके देखें तो मेरा मानना है कि, मैं गलत भी हो सकता हूँ, विदेशी निवेशक यहां के बारे में अधिक आशावादी हैं, क्योंकि पूरे विश्व में देखें तो वे अन्य स्थानों की तुलना में अपेक्षाकृत भारत जा सकते हैं। प्रणय, इन सब में जो दूसरी बात है, उसके लिए मैं आपको दोष देना चाहूंगा, वह यह कि हम यह भूल गए हैं कि हमारे पास एक नया भारत है जिसमें प्रौद्योगिकी, गतिमानता, पहल, ऊर्जा सब कुछ है लेकिन हो सकता है कि हम पुरानी मैनुफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था के कुछ अधिक ही वशीभूत हो गए हों।

एनडीटीवी : बहुत बढ़िया, लेकिन यहां भी क्या हमें अलीबाबा मिल पाएंगे ? क्या यह 300 बिलियन डालर की कंपनी थी ?

रघुराम राजन : भारत में ये सब बहुत उपयुक्त है, मेरे कहने का मतलब है कि मेट्रो में एक बड़ी दुकान लगाने की लागत पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि काफी अवसर है क्योंकि जमीन आदि कीमतें वैसी हैं किंतु भंडारगृह रखना, अनेक कस्बों का उभारना, ई-कॉमर्स इसका उत्तम समाधान है। इस प्रकार एक छोटे से कस्बे में कोई नेट देखता है, उसपर ये सारी चीजें देखता है और आज वे इन चीजों तक पहुंच सकते हैं जिस तक उनकी पहुंच पहले कभी नहीं थी।

एनडीटीवी : मैं आपको सूरत की एक महिला का उदाहरण देना चाहूंगा, अधेड़ उम्र की औरत जो साड़ी डिज़ाइन करती है। कई वर्षों से वह यह काम कर रही है, जो एक के बाद अनेक थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता के पास यह कहने के लिए चक्कर लगाती है कि वे उसकी साड़ी अपने पास रख लें। उन्होंने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। उसे यह कार्य बहुत ही मुश्किल लग रहा था। आप जानते हैं कोई भी मेरी साड़ी नहीं देख सकता था। उसने उस साड़ी को एक ई-कॉमर्स साइट्स पर रखा और आज वह बिना किसी की मेहरबानी के 20 करोड़ रुपए सालाना कमाती है, इसलिए ऐसी स्थिति एक आम आदमी को, किसी उद्यमी को प्रभावित करती है।

अरविंद सुब्रमणियन : इसलिए भारत के इस गतिमान स्वरूप को नज़र से ओझल न होने दें। मेरा यह कहना नहीं है कि यह भारत की समस्त चुनौतियों का उत्तर है। मेरे विचार से मैनुफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। लेकिन वहीं पर गतिमानता, प्रतिभा, प्रौद्योगिकी, उपयोग की भारी संपदा भी है, रघु और मैंने बहुत पहले इसके बारे में कुछ लिखा था, भारत का मंथन, उक्त चीजें भारत के मंथन का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।

एनडीटीवी : लेकिन यह कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता है कि यहां वहां कुछ-कुछ संरचनागत, नियमगत, रेगुलेशन, लोगों की समस्याएं हैं, आपको केवल बाज़ार या भंडारगृह ही नहीं चाहिए जिसका समाधान हमें करना है। हमें अन्य देशों से सीखना है, या तो हूबहू लाएं या फिर उससे प्रेरित हों।

रघुराम राजन : मेरे विचार से केंद्रीय बैंक और सरकार दोनों रेगुलेटरों के कान खुले हुए हैं और वे इस संबंध में कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने ऐसे उद्यमियों के साथ समय बिताया है जो यह तय करना चाह रहे थे कि आप क्या कहते हैं, आपको ऐसा क्या लगता है कि यहां अपने उद्यम को निगमित करने के बजाय सिंगापुर में जाकर करते हैं ? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं ? कुछ चीजों का निर्धारण तो हम सीधे-सीधे कर सकते हैं और कुछ में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वे अन्य बहुत सी चीजों से जुड़ी होती हैं। मेरा मानना है कि हम यह अच्छी तरह समझ गए हैं कि हमें कारोबारी वातावरण आसान बनाना होगा और बेहतर रेगुलेटर्स रखने होंगे, ऐसा नहीं कि कोई रेगुलेशन न हो, बेहतर हो, जो उपयुक्त हो, हलका हो किंतु अच्छी तरह से जिसका प्रवर्तन हो। हमारी पुस्तिका में जो है उसे लागू करना है और कंपनी के साथ हमारी एक नाराजगी यह थी

कि वह फेमा नियमों का उल्लंघन कर रही थी और ग्राहकों को आसान सेवा प्रदान करने की दृष्टि से हमने कहा कि नियमों का उल्लंघन करना बंद करें। हमने यह समाधान निकाला कि या तो नियम बदल दिए जाएं या फिर नियमों का पालन करने के लिए नये तरीके अपनाए जाएं।

एनडीटीवी : यह वाकई किसी चीज के प्रति देखने का ताजा तरीन तरीका है।

अरविंद सुब्रमणियन : इस बात में मैं यह भी जोड़ना चाहता हूँ कि हलके रेगुलेशन बेहतर होते हैं, किंतु भारतीय अर्थव्यवस्था की इन नई संस्थाओं में सरकार की निष्क्रियता का उतना ही भारी अंतराल है जितना कि सक्रियता होनी चाहिए थी।

एनडीटीवी : वैसे भी यह बात आमतौर पर सही है। प्रत्येक दिन संसद में, हम संसद में कार्य करने का एक दिन खो देते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये तो देश के लिए एक खेल है।

एनडीटीवी : एक अन्य मुद्दा भी है, जिसे बहुत से लोग उठा रहे हैं, एक कहावत है कि यदि टूट जाए तो जोड़ो मत। रिज़र्व बैंक ने वर्षों से बड़े संदर ढंग से कार्य किया है, इस समय हमारे पास रिज़र्व बैंक के महान गवर्नर हैं, जिनकी दुनिया तारीफ करती है, उसपर भी आप एमपीसी क्यों बनाना चाहते हैं, मौद्रिक नीति समिति उसके कार्यों में हस्तक्षेप करेगी ? क्या यह टूटने जैसा नहीं है।

रघुराम राजन : वस्तुतः इस संबंध में मैं टोकना चाहता हूँ

एनडीटीवी : नहीं, नहीं

रघुराम राजन : मैं बीच में इसलिए टोकना चाहता हूँ कि वास्तव में मैं एमपीसी चाहता हूँ।

अरविंद सुब्रमणियन : यही बात वह कहना चाह रहे थे।

एनडीटीवी : अब आप भी राजनैतिक दृष्टि से बिलकुल सही कह रहे हैं, वे भी हंस रहे हैं।

रघुराम राजन : इसके लिए मैं लंबे समय से कहता रहा हूँ। यह कुछ ऐसी चीज है जिसकी स्थापना किया जाना महत्वपूर्ण है, रिज़र्व बैंक की स्वतंत्रता भविष्य में थोड़े समय के बाद व्यक्तियों से परे होगी और इसके केवल तीन, चार कारण हैं, पहला, जब आपके पास एक समिति होगी तो सबसे पहले आपको अनेक मत प्राप्त होंगे, इसलिए इसमें कोई मैं नहीं होगा, यह लोगों का एक समूह होगा जिन्होंने विचार किया और आपको सामूहिक राय प्राप्त हो गई। उम्मीद है कि सामूहिक राय समय के साथ-साथ वैयक्तिक राय से बेहतर सिद्ध होगी, संभवतः दूसरा कारण, यदि आपके पास सही व्यक्ति तो यह समस्या फिर हमेशा के लिए रहेगी।

एनडीटीवी : परेशानी तो यही है, सरकार 7 में से 4 लोगों को नियुक्त करेगी।

रघुराम राजन : सरकार ने हमेशा रिज़र्व बैंक के गवर्नर को नियुक्त किया है।

अरविंद सुब्रमणियन : अच्छी पसंद, आप सदैव यह कह सकते हैं।

एनडीटीवी : हमेशा नहीं, लेकिन इस समय तो है।

रघुराम राजन : यह यथोचित रूप से अच्छा रहा है . . . .

अरविंद सुब्रमणियन : ये हमेशा विनम्र रहे हैं।

एनडीटीवी : मुझे नहीं लगता कि अफसर शाह लोगों के इस तरह का महत्वपूर्ण पद क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। वे विचार करने में ही पांच वर्ष लगा देंगे।

रघुराम राजन : डॉ. वाई बी. रेड्डी महान गवर्नर थे।

एनडीटीवी : कई थे

रघुराम राजन : मुद्दा यह है कि अनेक राय चाहिए। दूसरा यह कि आपके पास छह लोग हैं, एक चला जाता है, छह, बारह जो भी संख्या हो . . . .

एनडीटीवी : क्या यह संख्या छह है ? मैं समझता था कि सात है

रघुराम राजन : संख्या जो भी हो सरकार इसकी घोषणा करेगी।

अरविंद सुब्रमणियन : संख्या के बारे में चर्चा की जा रही है।

रघुराम राजन : चर्चा की जा रही है।

एनडीटीवी : मुझे तो यह अनूठी ख़बर मिल गई है।

रघुराम राजन : नहीं, आपको नहीं मिली है।

एनडीटीवी : एक छोटी सी ही ख़बर

रघुराम राजन : चाहे जो संख्या हो, वे लोग यदि उनमें से एक अनुपस्थित भी रहते हैं तो शेष मौद्रिक नीति की निरंतरता के स्रोत सिद्ध होंगे। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय बैंक का महत्व क्या है।

एनडीटीवी : गवर्नर की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है।

रघुराम राजन : ऐसा नहीं है, मैं तीसरे मुद्दे पर आ रहा हूँ। 6 लोगों पर दबाव डालना अधिक मुश्किल है बजाय एक व्यक्ति पर दबाव डालने के। आपने अभी-अभी उद्योगपतियों की दुर्दशा के बारे में बताया। मैं घर जाऊंगा इसके बारे में सोचूंगा कि इसका समाधान कैसे किया जाए आदि। अलग-अलग लोगों की राय भी भिन्न होगी। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी। अब यह मुद्दा कि कौन नियुक्ति आदि करेगा, निरंतरता बनाए रखने से जुड़ा है और मैं समझता हूँ कि हमें तय करना चाहिए और काफी हद तक सरकार के साथ इस बात पर सहमति बन चुकी है कि इसे किस प्रकार से किया जाए। यह मुद्दा कैबिनेट के माध्यम से जाएगा उसके बाद विधायी के माध्यम से, हो सकता है कि उसमें संशोधन भी हो, लेकिन काफी सहमति है और सरकार को इस प्रक्रिया का अत्यधिक समर्थन है।

अरविंद सुब्रमणियन : मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप सरकार के नज़रिये से देखें तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक हमारी एक महान और अतुलनीय संस्था है और हम उसे उसी तरह बनाए रखना चाहते हैं और यदि कोई कार्य करेंगे तो मिलकर करेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे।

एनडीटीवी : लेकिन क्या आप सरकार को नकार देंगे, ठीक है ?

अरविंद सुब्रमणियन : हमारे बीच कोई विरोध नहीं है। एक मौद्रिक नीति समिति स्थापित की जाएगी।

एनडीटीवी : यहां चर्च और प्रशासन जैसी स्थिति रहेगी। इसपर चारों तरफ से चिंता व्यक्त की जा रही है और यह संस्था बहुत बढ़िया तरीके से कार्य कर रही थी, मेरी समझ से गवर्नर की स्वतंत्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

रघुराम राजन : मैं समझता हूँ कि गवर्नर अभी भी स्वतंत्र ही रहेगा। लेकिन मेरा यह विश्वास है कि यदि ऐसी कोई संरचना तैयार की जाती है जिसपर व्यापक चर्चा हो चुकी है, तो वह एक स्वतंत्र सत्ता होगी, और आप को याद रखना होगा कि हर बार लोगों की नियुक्ति सरकार करती है, लेकिन यदि किसी संस्था में जब नियुक्त करती है तब वे ऐसे लोग होते हैं जो निष्ठावान होते हैं, वे खास होते हैं और संस्था के हितों को अंगीकार कर लेते हैं क्योंकि उनकी नियुक्ति उस संस्था के उद्देश्यों के अनुसार चलाने की होती है। ऐसा नहीं है कि नियुक्त किए गए व्यक्ति को जंजीर से बांध दिया जाएगा, मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, गवर्नर की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, किंतु सरकार और रिज़र्व बैंक के बीच मतभेद बने रहे हैं।

एनडीटीवी : ऐसा तो नहीं होता है कि आप खिन्न हो गए हैं और दरों को कम कर दें और यह कहें कि अब सारे लोग उसी में फंसे रहें ?

अरविंद सुब्रमणियन : इस बारे में मैं समझता हूँ कि फ्रांसिस फुकुयामा के कथन का अनुगमन करना होगा जिन्होंने पुस्तक 'एंड आफ हिस्ट्री' लिखी है, उन्होंने बहुत अच्छा मुहावरा इस्तेमाल किया है कि चीन में अच्छे बादशाह और खराब बादशाह की समस्या है, इसलिए जब आप एक व्यक्ति होते हैं तब आप अच्छा या बुरा नहीं जानते हैं ? मेरी समझ से हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे है . . . .

एनडीटीवी : सरकार ने आपको सच्चाई जानने के लिए कब अपने साथ लिया था।

अरविंद सुब्रमणियन : हम रिज़र्व बैंक के साथ एक अच्छा बादशाह बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु एक ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहते है जो उत्तम संस्थागत विचार प्रदान करे और गवर्नर की सत्ता स्वतंत्र हो।

एनडीटीवी : क्या इससे आपको उस बात की याद नहीं आती जब न्यायव्यवस्था बनाम सरकार हुई थी, जिसमें उन्होंने कुछ न्यायाधीशों की नियुक्तियों में परिवर्तन करना चाहा था और उन्होंने उसका विरोध किया था ? क्या आप विधि में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे है? हो सकता है कि इस समय सरकार अच्छी हो, लोग अच्छे हो और अगले 10 वर्ष तक कार्य करें और उसके बाद मूढ़ सरकार आ जाए और उस समय गवर्नर को नुकसान पहुंचाएं।

रघुराम राजन : यह बहुत स्पष्ट है कि इस नई संरचना से स्वतंत्रता अधिक होगी, सरकार चाहे जो हो।

एनडीटीवी : सरकार करेगी।

रघुराम राजन : क्योंकि आप रातोंरात पूरी संरचना को नहीं बदल सकते। लोगों की कार्यावधि होगी और इसतरह नीति की निरंतरता बनी रहेगी। उस समय जब लोग छोड़ रहे होंगे और उस समय भी नई सरकार आ रही होगी। इसलिए थोड़ा बहुत लक्ष्य करना जो स्थिर हो, एक समिति बनाना जो स्थिर हो, ये सब संस्थागत बातें हैं और मेरी समझ से ये परिवर्तन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

एनडीटीवी : एक अंतिम प्रश्न।

श्रोता 5 : मोटे तौर पर देखें तो इस बात की उम्मीद कम ही रही है कि भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार एक-दूसरे के प्रति मित्रता के भाव से रहे हों। इस बारे में थोड़ा आगे की बात करते हैं, पिछली सरकार की समिति की सिफारिशें भी रही हैं, जैसे रंगराजन समिति जिसको यह संस्तुति की थी कि भारिबैंक बजट के बारे में, अन्य मामलों के बारे में सरकार से परामर्श भी करे। हमें बाद में ये सब बातें क्यों नहीं दिखाई दीं। हमें वित्तीय या राजकोषीय नीति तथा मौद्रिक सामान्य रूप से एक साथ क्यों नहीं दिखाई देती हैं ?

एनडीटीवी : सामान्य रूप से आपको उनके साथ मिलकर बजट लिखना चाहिए।

रघुराम राजन : पहली बात तो यह है कि भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार के बीच मतभेद नहीं हैं, मैं ऐसी बात दुबारा सुनना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन कभी-कभी जैसे दो प्रेस में कुछ आ जाए, और छोटे-छोटे मतभेद या सामान्य मतभेद या व्यक्तित्व का टकराव गहरी समस्या पैदा कर देती है।

एनडीटीवी : एनडीटीवी पर तो नहीं।

रघुराम राजन : हमारी नियमित चर्चा होती रहती है, ऐसा नहीं है कि केवल मौद्रिक नीति से पहले हो। हमारी सरकार के साथ बात समस्त स्तरों पर बराबर चलती रहती है और हमारे बीच प्रायः बड़ी अच्छी समझ है, कभी-कभी थोड़े मतभेद होते हैं, तो उतना तो रहना ही चाहिए, क्योंकि हमारी नियुक्ति भी अलग दिखाई देने के लिए की गई है, क्योंकि इसका संचालन सरकार से ही होता है ।

अरविंद सुब्रमणियन : बिलकुल सही बात है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि आपको बहुत चिंता होनी चाहिए यदि हम मानक से कमतर चीजों के लिए असहमत होते हैं, आप इस बात के लिए उसी तरह चिंतित होंगे यदि हम प्रत्येक बातों पर सहमत हो जाते हैं और किसी भी चीज पर असहमत नहीं होते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि आप जो चाहते हैं उसपर हम केवल अपना अभिमत देते हैं, ठीक उसीप्रकार से जैसे किसी भी काम को करने के लिए उनके अभिमत होते हैं, हमारे पास इसकी प्रक्रियाएं हैं। सच तो यह है कि ये बातें फैलती हैं, उनकी समीक्षाएं होती है और उन पर चर्चाएं की जाती हैं आदि। और इस प्रक्रिया में मेरे पास रघु का नंबर है और उनके पास मेरा नंबर है।

एनडीटीवी : और दोनों एक-दूसरे का फोन कभी नहीं उठाते।

रघुराम राजन : मेरे विचार से महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार किसी को भी संस्था से हटाने का अधिकार रखती है, लेकिन वहां सरकार यह भी कहती है कि मेरे विचार ये हैं किंतु निर्णय आपका रहेगा। इस तरह सरकार अपने अभिमत सुनाती है लेकिन यह जरूरी है कि जिस संस्था को अभिमत सुनाती है वह संस्था उस संबंध में निर्णय ले और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की संस्कृति, ऐसे निर्णयों ने हमारे देश का निर्माण किया है, यह एक महत्वपूर्ण परंपरा है।

अरविंद सुब्रमणियन : इस परंपरा को बदलने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

एनडीटीवी : मैं समझता हूँ कि हमने पूरे 20 मिनट तक बात कर ली है, समय बीतता जा रहा है। एक प्रश्न है जो लोग मुझसे कहते हैं कि आपसे पूछा जाए। आप ऐसा क्या चाहेंगे कि रघुराम राजन जी आपके बजट में कोई एक चीज करें और आप क्या चाहेंगे कि अरविंद सुब्रमणियन जी आपकी मौद्रिक नीति में करें और फिर इसीके साथ हम अपनी बात समाप्त कर देंगे और हमारे 20 मिनट भी पूरे हो जाएंगे।

रघुराम राजन : हे ईश्वर, मुझे इस संबंध में सोचना पड़ेगा।

एनडीटीवी : उन्हें सोचने दीजिए, अरविंद सुब्रमणियन साहब आप ही पहले बोलिए।

अरविंद सुब्रमणियन : हो सकता है कि इससे संबंध और भी सौहार्दपूर्ण हो जाएं, लेकिन इस समय मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता, किंतु मेरे विचार से रिज़र्व बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे सरकार महत्व देती है।

एनडीटीवी : वे आपको एक चीज की सलाह दे सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं कहेंगे कि जाइये और छलांग लगा दीजिए - - -

अरविंद सुब्रमणियन : यह एक चीज है जो रघु नहीं कर रहे हैं, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था के भारतीय स्पर्धी पर तथा विनिमय दर पर निगरानी रखना जिसके बारे में आपने चिंता प्रकट की है।

रघुराम राजन : इसके बारे में सरकार पूरी कोशिश कर रही है, पहले से करती रही है, किंतु जीएसटी पारित होना एक महत्वपूर्ण संकेत होगा, जो न केवल घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी, कि हम कठिनाइयों को समाप्त करना चाहते हैं, भले ही चाहे जितनी मत भिन्नता क्यों न हो।

एनडीटीवी : यह राजनीति करने से परे का रास्ता है।

रघुराम राजन : यह राजनीति से आगे की बात है। यह आगे चलकर संवृद्धि स्थापित करने व सुनिश्चित करने की बात है, जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि जीएसटी में प्रयास किया जा रहा है।

एनडीटीवी : क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिसका वे प्रयास नहीं कर रहे हैं जिसे करना चाहिए ?

रघुराम राजन : मेरी समझ से यही बहुत है। यदि हम जीएसटी पारित कर सके तो इससे बहुत बड़ा संकेत जाएगा और बाहर से आने वाली किसी भी प्रकार की बाहरी अस्थिरता के प्रति अत्यधिक संरक्षण होगा। जैसाकि आपने कहा कि हम मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, लेकिन यही उपयुक्त समय है संकेत देने का और यह उत्तम कार्य होगा ।

अरविंद सुब्रमणियन : इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ, सरकार की ओर से यह केवल संदेश मात्र नहीं होगा, बल्कि सभी वर्गों एवं सभी पार्टियों के लिए सचमुच समावेशी भावना होगी और हमें राष्ट्रीय हित को संकीर्ण बातों के ऊपर रखना होगा, इसलिए मैं रघु की बातों का समर्थन करता हूँ।

एनडीटीवी : आप दोनों को सुनना अदभुत था, बहुत-बहुत धन्यवाद।